जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

जनहितैषी अब janhitaishinews.com पर भी

R.N.I. No. 64278/96 वर्ष:29 अंक:146 दिनांक:29-09-2024 रविवार मूल्य : 1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 वडोदरा M

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 सितंबर, 2024 को जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में चल रहे जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के बीच एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

लेबनान के हिजबुल्लाह के समर्थक उस समय प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जब समूह के नेता हसन नसरल्लाह 9 अगस्त, 2022 को बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में एक विशाल स्क्रीन के माध्यम से उन्हें संबोधित करते हैं। हिजबुल्लाह ने 28 सितंबर, 2024 को पुष्टि की कि उसके नेता की मौत हो गई है,

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में वसुंधरा एवं शिवराज आगे

- संघ लगाना चाह रही है मोदी-शाह पर लगाम

- संजय जोशी का नाम पर सहमति नहीं

नई दिल्ली,(ईएमएस)। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर एक बार फिर चौंकाने वाला परिणाम देने की तैयारी में दिख रही है। ऐसे में यदि संघ की चलती है तो वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी। वैसे पार्टी आलाकमान वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के नामों को आगे कर विचार करने में लगे हुए हैं। वहीं संघ अब चाह रहा है कि मोदी और शाह पर लगाम कसी जाए और पार्टी के सभी लोग जिस नाम पर मोहर लगाएं उसे ही पार्टी अध्यक्ष बनाया जाए। इसे लेकर पार्टी और संघ में तनातनी की स्थिति बनी हुई है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चहुंओर चर्चाओं का दौर शुरु हो गया है। यहां पार्टी के शीर्ष सूत्रों की मानें तो पार्टी आलाकमान राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर गंभीरता के साथ विचार कर रहे हैं। वहीं पार्टी नेतृत्व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाह रहा है। इससे हटकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पहले ही संजय जोशी का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया जा चुका था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह उनके नाम पर सहमत होते नहीं दिखे हैं। मोदी और शाह की पहली पसंद शिवराज सिंह चौहान बन गए हैं, संघ की पसंद वसुंधरा राजे का नाम है। ऐसे में संघ नहीं चाहता कि अध्यक्ष पद को लेकर किसी तरह खींचतान हो या फिर विवाद उत्पन्न हो, इसलिए संघ ने इशारा कर दिया है कि पार्टी के सभी लोग जिसे चाहें उसे ही पार्टी अध्यक्ष बनाया जाएगा।

लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए माना जा रहा है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अब संघ की पसंद का ही होगा। इससे पार्टी में संघ का वर्चस्व बनाने में मदद मिलेगी। भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों में वर्तमान नेतृत्व के खिलाफ जो नाराजगी है, संघ उस नाराजगी को दूर करके पार्टी को एकजुट बनाने की दिशा में काम कर रही है। संघ के फार्मूले पर यदि पार्टी अध्यक्ष का चुनाव होता है तो संजय जोशी या वसंधरा राजे ही अगले अध्यक्ष हो सकते हैं, यदि मौजूदा पार्टी नेतृत्व की चली तो शिवराज सिंह के नाम पर सहमति बनेगी, जो आगे भी तनातनी का कारण बनेगा। वैसे वसुंधरा राजे पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही हैं।

नए अध्यक्ष के नेतृत्व में ही होगा महाराष्ट्र-झारखंड चुनाव

भारतीय जनता पार्टी के नये राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ही पार्टी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की रणनीति पर कार्य कर रही है। ऐसे में जो भी अध्यक्ष बनता है, उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी दोनों ही राज्यों में पार्टी को बड़ी जीत दिलवाना। सूत्रों की मानें तो अगले महीने में ही चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव घोषित कर सकता है, ऐसे में पार्टी के नये अध्यक्ष के लिए यह चुनौतीपूर्ण चुनाव नहीं होगा। समय कम होगा, और सभी को साधना कोई आसान बात नहीं होगी।

आठ बच्चों सहित 17 बांग्लादेशियों को वापस भेजा

-सीएम सरमा ने की असम पुलिस की तारीफ

दिसपुर (ईएमएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि असम पुलिस ने तड़के आठ बच्चों सहित 17 बांग्लादेशियों को सीमा पार वापस भेज दिया। सीएम सरमा ने भारत में रोहिंग्याओं को लेकर आगाह करते हुए कहा था कि घुसपैठ काफी बढ़ गई है और जनसांख्यिकीय आक्रमण का खतरा वास्तविक और गंभीर दोनों है। उन्होंने कहा कि असम भारत-बांग्लादेश सीमा के केवल एक हिस्से की रक्षा कर रहा है, लेकिन एक बड़ा क्षेत्र अभी भी असुरक्षित है।

असम पुलिस की तारीफ कर सीएम सरमा ने कथित घुसपैठियों के नाम भी बताए-हारुल लामिन, उमाई खुनसुम, मोहम्मद इस्माइल, संसिदा बेगम, रूफिया बेगम, फातिमा खातून, मोजुर रहमान, हबी उल्लाह, सोबिका बेगम। इसके पहले सरमा ने कहा था कि मैंने असम, झारखंड और बंगाल में जनसांख्यिकीय आक्रमण देखा है। सरमा ने कहा, जब जनगणना होगी, तब पूर्वी भारत के राज्यों की जनसांख्यिकी पर चौंकाने वाली खबरें आएगी।

उन्होंने कहा, असम में स्थिति अलग है, क्योंकि लोग जनसांख्यिकीय आक्रमण के बारे में बहुत जागरूक हैं। सरमा ने कहा कि अवैध विदेशियों के खिलाफ असम आंदोलन के दौरान, लोगों ने चेतावनी दी थी कि राज्य के सामने आने वाली समस्याएं अंततः पूरे देश को प्रभावित करेंगी, और हम देख रहे हैं कि अब ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि 2024 और 2019 की मतदाता सूची की तुलना की जाए तो जनसांख्यिकीय परिवर्तन स्पष्ट होगा।

वैक्सीन पर रिसर्च कर फंसे बीएचयू के 11 वैज्ञानिक

भारत बायोटेक ने 5 करोड़ की मानहानि का दावा किया

वाराणसी (ईएमएस)। भारत बायोटेक ने जर्नल और बीएचयू के 11 वैज्ञानिकों पर 13 सितंबर को 5 करोड़ की मानहानि का दावा किया है। इसके बाद इंटरनेशनल जर्नल ने भी इसकी समीक्षा का फैसला किया और इसे पब्लिक डोमेन से हटा लिया। इंटरनेशनल जर्नल नेचर के ड्रग सेफ्टी जर्नल के एडिटर ने बताया कि लोगों पर वैक्सीन के इफेक्ट को गलत तरीके से दिखाया गया है। बायोटेक द्वारा मानहानि का दावा किए जाने के बाद इस रिसर्च पेपर को वापस ले लिया गया है। इसे पब्लिक प्लेटफॉर्म से हटा लिया गया है। ये रिसर्च आईएमएस बीएचयू के फार्माकोलॉजी और जीरियाट्रिक विभाग में संयुक्त रूप से किया गया था।

बीएचयू के वैज्ञानिक प्रोफेसर शंख शुभ्रा चक्रवर्ती सहित 11 वैज्ञानिकों की टीम ने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन पर एक रिसर्च किया था। रिसर्च पूरी तरह टेलीफोनिक था। इसमें 635 किशोर और 291 वयस्क शामिल हुए थे। इसका रिसर्च पेपर 13 मई को कौवैक्सीन के सुरक्षा विश्लेषण (बीबीवी152) नाम से जर्नल में प्रकाशित हुआ था। जिसमें इसके साइड इफेक्ट की चर्चा थी और इसे एक साल में कम्प्लीट होना बताया गया था।

लोकसभा चुनाव के बीच आने से मचा था बवाल

13 मई 2024 को जर्नल में प्रकाशित होते ही देश में चल रहे लोकसभा चुनाव में विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी हो गया था। रिसर्च पेपर की प्रतियां प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई जाने लगी थीं। इस पर उसी समय आईसीएमआर ने प्रतिबंध की मांग की थी। क्योंकि इस रिसर्च में आईसीएमआर का भी नाम था। 28 मई को इस लिखित मांग के जवाब में वैज्ञानिकों ने नाम हटाने की बात कही थी।

बीएचयू ने झाड़ लिया था पल्ला, अधूरा बताया था

आईसीएमआर ने रिसर्च में नाम यूज करने पर आईएमएस बीएचयू के डायरेक्टर प्रोफेसर एसएन संखवार को नोटिस भेजा था। जिसमें पूछा था कि यह रिसर्च कैसे किया गया? डायरेक्टर ने इस पर एक जांच कमेटी बनाई थी। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस रिसर्च को ही अधूरा बताया था।

लोगों में सांस संबंधी इन्फेक्शन बढ़ रहा

स्टडी करने वाले शंख शुभ्रा चक्रवर्ती ने कहा कि हमने उन लोगों का डेटा कलेक्ट किया जिन्हें वैक्सीन लगे एक साल हो गया था। 1,024 लोगों पर स्टडी हुई। इनमें से 635 किशोर और 291 वयस्क शामिल थे। स्टडी के मुताबिक,304(47.9 प्रतिशत) किशोरों और124(42.6 प्रतिशत) वयस्कों में सांस संबंधी इन्फेक्शन (अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन) देखे गए। इससे लोगों में सर्दी, खांसी जैसी समस्याएं देखी गईं।

अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट , बच्चे समेत 3 जिंदा जले

सोनीपत(ईएमएस)। हरियाणा के सोनीपत में अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस आग में 3 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 3 शव बरामद कर लिए गए हैं। इनमें एक शव गांव की महिला का, जबकि दूसरा बच्चे का है, तीसरा एक अन्य महिला का है। फैक्ट्री में जोरदार धमाके के बाद ग्रामीणों को हादसे का पता चला। ब्लास्ट से साथ लगते मकानों की दीवारों में दरारें आ गई। जिस मकान में पटाखे बनाए जा रहे थे, वह भी ढ़ह गया और काम करने वाले मजदूर मलबे में दब गए। यहां 10-12 मजदूर काम कर हे थे।

हादसे में करीब 6 महिलाओं समेत 7 व्यक्ति बुरी तरह झुलस गए हैं। झुलसे मजदूरों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गयाहै।आगगैस सिलेंडर में लीकेज के कारण लगी थी। मकान गांव के बीचों बीच है और इसका मलबा हटाने की कार्रवाई जारी है। कुछ ही देर में आग फैल गई और उसमें काम कर रहे मजदूरों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। आग लगने के बाद गांव में अफरातफरी मच गई। ग्रामीणों ने उसमें काम कर रहे लोगों को बाहर निकाला। पुलिस ने मकान मालिक वेदप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। घायलों में इसकी बेटी भी शामिल है।

ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी

बंगलूरू(ईएमएस)। कर्नाटक की राजधानी बंगलूरू के ताज वेस्ट एंड होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस होटल को धमकी भरा ईमेल भेजा गया। मेल सामने आने के बाद बंगलूरू पुलिस जांच में जुट गई है। बंगलूरू पुलिस के डीसीपी शेखर एचटी ने होटलों को धमकी भरा ईमेल मिलने की पुष्टि की है। सूचना मिलते हुए तुंरत होटल की सुरक्षा बढ़ाने के साथ जांच शुरू कर दी गई है। बम निरोधक दस्ता और शहर पुलिस की टीम होटल में पहुंच गई है।

मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव में सभी सीटों पर जीत तो बस शुरुआत - आदित्य ठाकरे

मुंबई (ईएमएस)।मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव में शिवसेना (यूबीटी) की युवा शाखा 'युवा सेना ने प्रचंड जीत हासिल करते हुए सभी 10 स्नातक सीटें हासिल कर लीं तथा भाजपा से संबद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को आसानी से हरा दिया।इस जीत पर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव में सभी सीटों पर उनकी पार्टी की जीत तो बस शुरुआत है, इस तरह की जीत आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी दोहराई जानी चाहिए।

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के आवास 'मातोश्री के बाहर उत्साहित पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि सीनेट चुनाव के लिए मतदान केवल मुंबई में ही नहीं हुआ, बल्कि ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले में भी मतदान हुआ और यह जीत उनकी पार्टी के प्रभाव को दर्शाती है।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के साथ दो अलग-अलग मुठभेड़ में पुलिसकर्मी शहीद, दो आतंकवादी मारे गए

नई दिल्ली (ईएमएस)। जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में शनिवार की शाम को एक दूरस्थ ग्रामीण इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गया और एक सहायक उपनिरीक्षक घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि, कठुआ जिले के एक सुदूर गांव में सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। बिलावर तहसील के कोग-मंडली गांव में मुठभेड़ शाम को करीब साढ़े पांच बजे शुरू हुई। सुरक्षा बलों ने एक घर में आतंकवादियों के एक गुट के मौजूद होने की सूचना मिलने के बाद संयुक्त घेराबंदी की थी और तलाशी अभियान शुरू किया था। इसी बीच मुठभेड़ शुरू हो गई।

अधिकारियों ने बताया कि शुरू में गोलीबारी कुछ देर तक चली लेकिन बाद में दोनों पक्षों के बीच भारी गोलीबारी शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि गोलीबारी में एक पुलिस हेड कांस्टेबल शहीद हो गया और सहायक उपनिरीक्षक घायल हो गया। अधिकारियों के अनुसार अंतिम सूचना मिलने तक गोलीबारी जारी थी। वहीं कुलगाम जिले में भी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए और जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी सहित पांच सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ कुलगाम के अदिगाम इलाके में हो रही थी।

मुंबई में आतंकी हमले की आशंका

फेस्टिवल सीजन से पहले खुफिया एजेंसियों की चेतावनी

मुंबई(ईएमएस)। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. खुफिया एजेंसियों ने फेस्टिवल के मौके पर हमले की आशंका जताई है. इस संभावित खतरे के मद्देनजर, शहर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद किया जा रहा है. महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा जांच बड़े पैमाने पर की जा रही है. खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर शहर में भीड़भाड़ वाले स्थानों और धार्मिक स्थलों को मॉक-ड्रिल किया जा रहा है और तमाम क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने इलाके में खास ध्यान रखने को कहा गया है.

हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, मॉल्स और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. सुरक्षा बलों ने इन जगहों की जांच-पड़ताल तेज कर दी है. सुरक्षा सिस्टम को अधिक सक्षम बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. मुंबई पुलिस ने एक बयान में कहा कि हमें भीड़भाड़ वाले स्थानों और धार्मिक स्थलों पर मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया गया है. सभी डीसीपी को अपने-अपने क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।

महाराष्ट्र में 26 नवंबर के पहले होंगे विधानसभा चुनाव

- त्योहारों को ध्यान में रखकर होगा तारीखों का ऐलान

मुंबई(ईएमएस)। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इसके पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तारीखों का ऐलान अगले महीने होने की उम्मीद है। राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एस एस संधू दो दिन के महाराष्ट्र दौरे पर हैं। उन्होंने यहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके अलावा उन्होंने शिवसेना, शिवसेना यूबीटी, भाजपा, एनसीपी, एनसीपी(एसपी), मनसे, बसपा, आप समेत 11 पार्टियों से मुलाकात की। सभी पार्टियों ने मांग की है कि दिवाली, देव दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों को ध्यान में रखकर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए।

महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 25 अनुसूचित जनजाति के लिए और 29 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए चुनाव इससे पहले पूरे करने होंगे। राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 9.59 करोड़ है, जिसमें पुरुष मतदाता 4.59 करोड़ और महिला मतदाता 4.64 करोड़ हैं। पहली बार वोट देने वाले, विशेष रूप से 18-19 वर्ष के युवा मतदाताओं की संख्या लगभग 19.48 लाख है। हमने महाराष्ट्र सरकार से उन अधिकारियों का तबादला करने का अनुरोध किया है, जो अपने गृह जिले या मौजूदा पोस्टिंग में 3 साल से अधिक समय से सेवा दे रहे हैं। यह वोटर्स का अधिकार है कि उन्हें पता हो किस कैंडिडेट का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। पार्टियों को अपने कैंडिडेट के बारे में ये जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए।

पश्चिम एशिया में टेंशन ऑल टाइम हाई...हिज्बुल्लाह पर 10 दिनों का सबसे भीषण हमला,

लेबनान में हेडक्वार्टर 80 टन बम से उड़ाया, हिज्बुल्लाह चीफ नसरल्लाह ढेर

बेरूत(ईएमएस)। इजराइली हमले में हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने शनिवार को यह दावा किया है। इजराइल ने 27 सितंबर को लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बंकर बस्टर बम से हवाई हमला किया था। तब नसरल्लाह भी यहीं मौजूद था। आईडीएफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि अब दुनिया को नसरल्लाह से डरने की जरूरत नहीं है। वह आतंक नहीं फैला पाएगा। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से अब तक नसरल्लाह की मौत की पुष्टि नहीं हुई है।

इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच लड़ाई लगातार भीषण होती जा रही है जिसकी कीमत लेबनान के आम लोग भी चुका रहे हैं. भारतीय समयानुसार शुक्रवार देर शाम इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एक के बाद एक कई एयरस्ट्राइक कीं. ये हमला यूएनजीसी में नेतन्याहू के भाषण के बाद हुआ है. इसे इजरायल का लेबनान में सबसे भीषण हमला माना जा रहा है. इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच लड़ाई लगातार भीषण होती जा रही है जिसकी कीमत लेबनान के आम लोग भी चुका रहे हैं. भारतीय समयानुसार शुक्रवार देर शाम इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एक के बाद एक कई एयरस्ट्राइक कीं. ये हमला यूएनजीसी में नेतन्याहू के भाषण के बाद हुआ है. इसे इजरायल का लेबनान में सबसे भीषण हमला माना जा रहा है. इस हमले के बाद आसमान में धुएं के गुबार छा गए. इजरायल ने बेरूत स्थित हिज्बुल्लाह के मुख्यालय पर भी हमला किया. ये मुख्यालय एक रियाशी इमारत के नीचे था. बताया जा रहा है कि इसमें हिज्बुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने बंकर बनाया हुआ था. पहले बताया गया था कि बंकर में नरसल्लाह हो सकता है. हालांकि सूत्रों की मानें तो हिज्बुल्लाह की तरफ से इसका खंडन कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि हमले से पहले इजरायल ने अमेरिका को भी इसकी जानकारी दी थी. इन हमलों में 6 इमारते पूरी तरह तबाह हो गईं.

इजराइल ने नसरल्लाह के अलावा उसकी बेटी जैनब की मौत का भी दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह चीफ की बेटी का शव उस कमांड सेंटर के मलबे में मिला है जिस पर इजराइल ने हमला किया था। उन्होंने कहा कि लेबनान के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। इजराइली सेना ने लेबनान में बेरूत समेत कई इलाकों पर दूसरे दिन भी मिसाइल हमले किए हैं। इजराइल ने बेरूत के दहियाह शहर में रहने वाले लोगों को तुरंत इलाका खाली करने को कहा है। इजराइली सेना का कहना है कि इन जगहों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह, इजराइल पर हमले के लिए कर रहा है।

इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 2006 के बाद सबसे भयानक लड़ाई छिड़ी है। 2006 में लेबनान पर हुए इजराइली हमले में हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 17 सितंबर को लेबनान पर पेजर अटैक हुआ था। इसके ठीक एक दिन बाद पेजर और वॉकी-टॉकी में भी विस्फोट हुए थे। हिजबुल्लाह और लेबनान ने इजराइल को इन हमलों का जिम्मेदार माना था। तब से इजराइल लगातार लेबनान में मिसाइल हमले कर रहा है। अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, इजराइली मिसाइल हमलों की वजह से लेबनान में 700 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोडक़र जाना पड़ा है। इजराइल ने लेबनान में चलाए जा रहे ऑपरेशन को नॉर्दर्न एरोज नाम दिया है। इजराइली डिफेंस फोर्स ने 23 सितंबर को लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया था। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की थी। इनमें 10 हजार रॉकेट बर्बाद करने का दावा किया गया। इस हमले में 569 लोगों की मौत हुई।

आईडीएफ का कहना है कि वह वर्तमान में बेरूत के दहियाह उपनगर में तीन इमारतों पर हमला कर रहा है, जहां हिजबुल्लाह ने एंटी-शिप मिसाइलों का भंडारण किया हुआ है। सेना ने कहा कि हमलों के बारे में आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी। इससे पहले, आईडीएफ ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में तीन इमारतों के आस-पास के नागरिकों को चेतावनी दी थी कि उन पर जल्द ही हमला किया जाएगा। आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नागरिक इमारतों के नीचे भूमिगत भंडारण सुविधाएं हैं, जहां हिज्बुल्लाह ने तट से समुद्र तक मिसाइलें, हथियार रखे हैं जो इजरायल और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के लिए खतरा हैं।

इजरायल ने बेरूत हवाई अड्डे के नियंत्रण टॉवर की प्रसारण फ्रीक्वेंसी पर कब्जा किया और एक ईरानी विमान को लेबनान में उतरने से रोकने का आदेश दिया है। लेबनान के एमटीवी नेटवर्क ने हाल ही में परिवहन और लोक निर्माण मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया है (जिसका नेतृत्व हिज़्बुल्लाह के मंत्री अली हमिया कर रहे हैं) कि इजरायल ने बेरूत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की प्रसारण फ्रीक्वेंसी पर कब्जा कर लिया है और हवाई अड्डे को आदेश दिया है कि एक ईरानी विमान को उतरने से रोका जाए। यदि इस आदेश का पालन नहीं किया गया, तो बल प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद, लेबनान के परिवहन मंत्री (जिनका संबंध हिज्बुल्लाह से है) ने ईरानी विमान को बेरूत में न उतरने का आदेश दिया।

इजरायली सेना ने बेरुत के अल-बराजनेह और अल-हदाथ इलाकों के निवासियों को तुरंत अपने घर छोडऩे और 500 मीटर से अधिक दूर जाने का आदेश दिया है, क्योंकि हिज़्बुल्लाह पर इजरायली हमले जारी हैं। इजरायली सेना के अरबी भाषा के प्रवक्ता अवीचाय अद्राई ने शनिवार को एक बयान में कहा, आप हिज़्बुल्लाह के ठिकानों के पास हैं, और अपनी और अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए आपको तुरंत इमारतों को खाली कर देना चाहिए और 500 मीटर से कम दूरी तक नहीं रुकना चाहिए। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश इजरायली हमलों के बढ़ते खतरों के बीच दिया गया है।

लेबनान में, विशेषकर अपने शिया समर्थकों के बीच हसन नसरल्लाह सुप्रीम लीडर की साख रखता था। उसे किसी देश के साथ युद्ध छेडऩे या शांति बहाली का निर्णय करने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति के रूप में देखा जाता था। साल 2006 में भी लेबनान पर इजरायली हमले में हसन नसरल्लाह के मारे जाने का दावा किया गया था। हालांकि, वह कुछ दिनों बाद सही सलामत सामने आया था। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजरायली हमले के बढऩे की आशंका को देखते हुए बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में स्थित अस्पतालों को खाली करने का आदेश दिया है। उन मरीजों को भर्ती नहीं करने के लिए कहा गया है, जिनकी स्थिति गंभीर नहीं है। ताकि संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों से स्थानांतरित होने वाले मरीजों के लिए अस्पतालों में जगह बनाई जा सके।

जिरीबाम में हिंसा, मैतेई गांव पर फायरिंग

चुराचांदपुर-कांगपोकपी में 3 दिनों का बंद

इंफाल(ईएमएस)। मणिपुर के जिरीबाम जिले में शनिवार को फिर हिंसा हुई। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध उपद्रवियों ने सुबह करीब 11.30 बजे मोंगबुंग मैतेई गांव में अंधाधुंध फायरिंग की। गांव के वालंटियर ने जवाबी कार्रवाई की। फिलहाल गोलीबारी जारी है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। दूसरी तरफ, चुराचांदपुर और कांगपोकपी जिलों में आज बंद का दूसरा दिन है। इसके कारण बाजार बंद रहे। सडक़ें वीरान दिखीं। अधिकारियों ने बताया कि कुकी-जो समूहों ने दोनों जिलों में रविवार, 29 सितंबर तक बंद का आह्वान किया है।

इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम और कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन सहित अन्य कुकी समुदाय सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह के बयान का विरोध कर रहे हैं। कुलदीप सिंह ने 20 सितंबर को दावा किया था कि मणिपुर में म्यांमार से 900 कुकी उग्रवादी घुस गए हैं। कुलदीप सिंह के मुताबिक, ये उग्रवादी ड्रोन बम, प्रोजेक्टाइल, मिसाइल और गोरिल्ला युद्ध में ट्रेंड हैं। ये 30-30 लोगों के ग्रुप में हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में छिपे हुए हैं। वे 28 सितंबर के आसपास मैतेई गांवों पर हमले कर सकते हैं। हालांकि, राज्य सरकार ने 25 सितंबर को ऐसे किसी हमले का दावा वापस ले लिया था।

भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद जब्त

मणिपुर पुलिस ने शनिवार को बयान जारी कर बताया कि सुरक्षाबलों ने तीन जिलों से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी जब्त किया है। मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स की एक जॉइंट टीम ने कांगपोकपी जिले के लोइचिंग रिज से दो .303 राइफल, मैगजीन के साथ एक 9 मिमी पिस्तौल, कारतूस, चार हैंड ग्रेनेड, दो डेटोनेटर और एक देसी मोर्टार और लंबी दूरी का इम्प्रोवाइज्ड मोर्टार जब्त किया है। पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के सुरक्षाबलों ने चुराचांदपुर जिले के गोथोल गांव में एक अन्य सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान दो मोर्टार जब्त किए गए, जिन्हें स्थानीय तौर पर पम्पी कहा जाता है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ग्रेट निकोबार द्वीप में मेगा इन्फ्रा परियोजना को दी गई मंजूरी पर सवाल उठाया

नई दिल्ली (ईएमएस)। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को एक और पत्र लिखकर ग्रेट निकोबार द्वीप में मेगा इन्फ्रा परियोजना को दी गई मंजूरी पर फिर से विचार करने को कहा है। कांग्रेस महासचिव ने ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी पर पुनर्विचार करने के लिए सौंपे गए एक उच्चस्तरीय समिति के आचरण, संरचना और निष्कर्षों पर भी आपत्ति जाहिर की है।

जयराम रमेश ने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का यह इनकार करना कि निकोबार परियोजना क्षेत्र का कोई भी हिस्सा निर्माण के लिए प्रतिबंधित तटीय क्षेत्रों में आता है, एक नाटकीय यू-टर्न था। उन्होंने पूछा कि प्रस्तुत नए तथ्यों पर क्या विश्वास किया जा सकता है? केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ग्रेट निकोबार द्वीप बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए दी गई मंजूरी ने द्वीप तटीय विनियम क्षेत्र अधिसूचना, 2019 का उल्लंघन नहीं किया है। इसमें यह भी कहा गया कि परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी पर पुनर्विचार करने के लिए एनजीटी के आदेशों का पालन किया गया है। सरकार के इस स्पष्टीकरण के बाद ही जयराम रमेश ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा था।

रमेश ने कहा कि वह आश्चर्यचकित थे कि एनजीटी की ओर से लचीलापन देने के बावजूद एचपीसी ने किसी स्वतंत्र संस्थान या विशेषज्ञों के साथ बात नहीं की। एचपीसी में नीति आयोग के सदस्य परियोजना की कल्पना करने वाले लोग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम जो परियोजना को लागू कर रहा था और पर्यावरण मंत्रालय जिसने मंजूरी दी थी शामिल थे।

जयराम रमेश ने कहा कि एचपीसी ने भी एनजीटी के निर्देशों को कमजोर कर दिया और परियोजना की मंजूरी और पर्यावरणीय मुद्दों का कोई सार्थक और व्यापक पुनर्मूल्यांकन नहीं किया। इसके अलावा, उन्होंने मंत्रालय के एचपीसी की रिपोर्ट को गुप्त रखने के तर्क पर भी सवाल उठाया। रमेश ने कहा कि मैं इसे नहीं समझता, जब मंजूरी देने की मूल प्रक्रिया को ही अधिकार प्राप्त और गोपनीय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था, तो कैसे एक समीक्षा जो भी त्रुटिपूर्ण हो और वह भी अदालत ने अनिवार्य की हो, इस प्रकार वर्गीकृत की जा सकती है।

पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी हिंदुस्तान में हो शामिलः रिजवी

- पीएम मोदी व योगी मिलकर कर सकते हैं अखंड भारत का सपना पूरा

बरेली,(ईएमएस)। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। इसमें उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान का समर्थन किया जो उन्होंने पीओके को लेकर कही थी। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर सीएम योगी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और वहां भाषण दिया। सीएम योग

जन हितैषी

हरियाणा विधानसभा चुनाव में सच और झूठ की लड़ाई?

हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम स्तर पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को हरियाणा के चुनाव प्रचार के लिए कार्यकर्ताओं के साथ ऑनलाइन संवाद किया। इस संवाद पर उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, कांग्रेस का आधार सिर्फ झूठ बोलने का है। कांग्रेस बड़े-बड़े झूठे दावे कर रही है। कांग्रेस के झूठे दावे का करंट कमजोर हो चुका है। मोदी ने कांग्रेस के ऊपर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस अधिकतर समय गुटबाजी और कांग्रेस नेताओं का हिसाब चुकता करने में बीतता है। कांग्रेस जनता के मुद्दों से दूर हो गई है। हरियाणा की जनता को कांग्रेस के झूठ पर विश्वास नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस यदि धोखे से जीत भी गई, तो यहां गांधी परिवार और उनके जीजा का राज होगा। मोदी जी ने कहा कांग्रेस की आंतरिक कलह से हरियाणा का बच्चा-बच्चा परिचित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को झूठी पार्टी बताते हुए, भाजपा कार्यकर्ताओं से हरियाणा विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ युद्ध करने का शंखनाद किया है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में झूठ को लेकर कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं।उससे ऐसा लगता है, महाभारत की युद्ध भूमि में एक बार फिर से धर्म और अधर्म अर्थात झूठ और सच की लड़ाई लड़ी जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा के चुनाव प्रचार में पहली बार पहुंचे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक-एक झूठ पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी भारत में चीन का माल बेचना चाहते हैं। भारत में माल नहीं बनाना चाहते हैं। जिसके कारण हरियाणा के युवाओं को ना तो नौकरी मिल रही है, नाही रोजगार मिल रहा है। चीनी कंपनियों की लिस्ट देखिए,भारत में उनका पार्टनर कौन है। नरेंद्र मोदी झूठ की मार्केटिंग पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। हरियाणा के युवा चोरी-छिपे भाग कर अवैध रूप से लाखों रुपए खर्च करके विदेश जा रहे हैं। बच्चे अपने माता-पिता से मिलने विदेश में चीख और चिल्ला रहे हैं। हरियाणा में कोई जॉब नहीं है। उन्होंने कहा मैं झूठ नहीं बोलता हूं। झूठ बोलना मोदी जी का काम है।10 साल से हरियाणा में भाजपा की सरकार है। इन्होंने कितना झूठ बोला है, यह हरियाणा की जनता को पता है। राहुल ने कहा कि हम कल जम्मू कश्मीर गए थे। वहां के सेव का व्यापार पूरी तरह से ढप्प हो गया है।कश्मीर के सेव का व्यापार अदाणी को मोदी जी ने दे दिया है। हरियाणा में नशे की गंगा बह रही है। हरियाणा के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। नौकरी नहीं मिल रही है। गुजरात के अदानी पोर्ट से हजारों किलो ड्रग्स भारत में बेचा जा रहा है। हरियाणा के युवा नशे के शिकार हो रहे हैं। राहुल गांधी ने 2013 से 2024 के बीच में बोले गए मोदी जी और भाजपा के झूठ की गिनती कराते हुए, राहुल ने अपने आप को सच बोलने वाला बताया। राहुल गांधी ने मोदी जी को झूठ बोलने वाला नेता बताया। हरियाणा के चुनावी मैदान में सच और झूठ की यह लड़ाई मतदाताओं के सहारे, कांग्रेस और भाजपा द्वारा लड़ी जा रही है। जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर झूठ बोलने के आरोप दोनों ही पक्षो द्वारा एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। उससे कौरव-पांडवों के बीच हुए युद्ध की यादें ताजा हो जा रही हैं। धर्म और अधर्म की लड़ाई, कौरव और पांडवों के बीच में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। ठीक वैसे ही हरियाणा विधानसभा चुनाव का युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि में होता हुआ दिख रहा है। हरियाणा के चुनाव में कौन सच्चा है, कौन झूठा है। इसका फैसला चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। राहुल गांधी ने अपने आप को युद्धिष्ठर के रूप में पहचान बनाने की कोशिश की है। हरियाणा की जनता ने पिछले 10 सालों में डबल इंजन की सरकारों का सच और झूठ दोनों का अनुभव किया है। कांग्रेस ने पिछले 10 सालों में क्या किया है। यह भी हरियाणा जनता ने देखा है। चुनाव परिणाम ही हरियाणा के झूठ और सच का फैसला करेंगे। हरियाणा के चुनाव में दोनों ही पार्टियों की विश्वसनीयता को लेकर जनता के मन में क्या है। चुनाव परिणाम के बाद पता लग जाएगा कौन झूठा और कौन सच्चा है।

आदिवासीयों को मुख्यधारा में जोड़ने की कोशिश

आदिवासी शब्द दो शब्दों आदि और वासी से मिल कर निर्मित है और इसका अर्थ है जो आदि काल से वास कर रहा हो अर्थात मूल निवासी।भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है। लोगों का ध्यान आकर्षित करने और मनोरंजन के लिए ही लोग आदिवासी समाज और सुसंस्कृति की ओर जाते रहे हैं। नतीजा हमारे सामने है उनके जीवन और रीति- रीवाजों के बारे में सनसनीखेज ब्योरे तो खूब मिलते हैं, पर उनके पारिवारिक जीवन की मानवीय व्यथा नहीं। उनके अलौकिक विश्वास, जादू टोने और विलक्षण अनूष्ठानों का आँखों देख हाल तो मिलता है, पर उनकी जिंदगी के हर सिम्त हाड़तोड़ संघर्ष की बहुरूपी और प्रमाणिक तस्वीर नहीं मिलते हैं। वे आज भी आदमी की अलग नस्ल के रूप में पेश किए जाते हैं। पुरातन संस्कृत ग्रंथो में आदिवासियों को अत्विका और वनवासी भी कहा गया है। संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति पद का उपयोग किया गया है। भारत के प्रमुख आदिवासी समुदायों में संथाल,गोंड, मुंडा, हो, बोडो, भील, खासी, सहरिया, गरासिया, मीणा, उरांव, बिरहोर आदि हैं। महात्मा गांधी ने आदिवासियों को गिरिजन (पहाड़ पर रहने वाले लोग) कह कर संबोधित किया था। इस पर वामपंथी मानविज्ञानियों ने प्रश्न उठाया था कि क्या ये मैदान में रहने वालों को मैदानी कहा जाता है। आदिवासी को दक्षिणपंथी लोग वनवासी या जंगली कहकर पुकारते हैं। इस तरह के नामों के पीछे बुनियादी रूप से यह धारणा काम कर रही होती है कि आदिवासी जंगल में वास करते हैं। वे देश के मूल निवासी हैं या नहीं तथा आर्य यहीं के मूल निवासी हैं या बाहर से आए हैं। भारत के मूलनिवासी कौन हैं, ये तमाम प्रश्न अभी भी भारतीय मानव विज्ञान में उलझा हुआ है। आमतौर पर आदिवासियों को भारत मे जनजातीय लोगों के रूप मे जाना जाता है। आदिवासी मुख्य रूप से भारतीय राज्यों उड़ीसा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल मे अल्पसंख्यक है जबकि भारतीय पूर्वोत्तर राज्यों में यह बहुसंख्यक हैं, जैसे मिजोरम। भारत सरकार ने इन्हें भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता दी है। अक्सर इन्हें अनुसूचित जातियों के साथ एक ही श्रेणी अनुसूचित जातियों और जनजातियों मे रखा जाता है जो कुछ सकारात्मक कार्रवाई के उपायों के लिए पात्र है। आदिवासी के अपने जनजातीय संप्रदाय हैं, जो इस्लाम या वैदिक हिंदू धर्म से अलग हैं पर तांत्रिक शैव के अधिक करीब हैं। 19 वीं सदी के दौरान ईसाई मिशनरियों द्वारा इनकी एक बडी- संख्या का परिवर्तन कराकर ईसाई बना दिया गया। माना जाता है कि हिंदुओं के देव भगवान शिव भी मूल रूप से एक आदिवासी देवता थे लेकिन आर्यों ने भी उन्हें देवता के रूप मे स्वीकार कर लिया। जब सदानी जातियों की मूल जाती नागवंशियों ने छोटानागपुर में राज्य बनाया था। खुखर राज्य के पहले राजा नागवंशी फणीमुकूट राय थे जिन्होंने मुंडाओं के सहयोग से राज्य की स्थापना की थी। नाग जाति के बारे में अभी तक पर्याप्त शोध नहीं हुए हैं किन्तु डॉ. अम्बेडकर तथा कई अन्य विद्वानों ने जो प्रमाण और साक्ष्य जुटाए हैं वे नाग जाति के इतिहास के अस्तित्व को स्पष्ट स्थापित करते हैं। नाग जाति बहुत सुसंस्कृत, बहादुर और शांतिप्रिय जाति रही हैं इस जाति ने गौतम बुद्ध के नेतृत्व में सैकड़ों वर्षों तक ब्राह्मण धर्म के जातिभेद और छुआ दृ छूत के खिलाफ संघर्ष किया था। हिन्दूओं ने अपने बहुत से पर्व दृ त्योहार इस जाती के संस्कृति से लिए हैं प्रसिद्ध राजा शशांक इसी नाग जाति के थे। आदिवासियों का जिक्र रामायण में भी मिलता है, जिसमें राजा गोहु और उनकी प्रजा चित्रकूट में श्रीराम की सहायता करती है। आधुनिक युग में एक आदिवासी बिरसा मुंडा, एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ एक धार्मिक नेता भी थे। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि भी एक भील आदिवासी थे। बहुत से छोटे आदिवासी समूह आधुनिकीकरण के कारण हो रहे पारिस्थिति की पतन के प्रति काफी संवेदनशील हैं। व्यवसायिक वानिकी और गहन कृषि दोनों ही उन जंगलों के लिए विनाशकारी साबित हुए हैं जो कई शताब्दियों से आदिवासियों के जीवन यापन का स्त्रोत रहे थे। आदिवासियों के विशेषज्ञ जे. जे. राय बर्मन के अनुसार आदिवासियों में सभी जातियां मूल आदिवासी जाति की केटेगरी में नहीं आतीं, इसी तरह मूल आदिवासियों में अनेक जनजातियां बाहर से आयी हैं। आज इन जनजातियों के लोग जहां रहते हैं वहां वे मूल रूप से नहीं रहते थे। मसलन मणिपुर के कूकी आदिवासी, मिजोरम के लूसिस जनजाति के लोग मूलतः दक्षिण चीन और चिन पर्वत के निवासी हैं। ये लोग कुछ सौ साल पहले ही स्थानान्तरित होकर भारत में आए हैं। कूकी को ब्रिटिश शासकों ने नागा बहुल इलाकों में बसाया था। जिससे नागा और वैष्णवपंथी मैइती जनजाति के बीच में बफर जॉन पैदा किया जाए। लूसी जनजाति से सैलो का संबंध है इसके मुखिया को ब्रिटिश शासकों ने ठेकेदार के रूप में बढ़ावा दिया जिससे वह मिजोरम में सड़कें बनाए। इस तरह अन्य जगह से लाकर बसाए गए आदिवासियों की बस्तियों का दायरा धीरे-धीरे त्रिपुरा तक फैल गया। जिसे इन दिनों तुइकुक के नाम से जानते हैं। यहा त्रिपुरा के राजा की नीति थी एउसने अपने राज्य में रियांग और चकमा जनजाति के लोगों को बाहर से लाकर बसाया। जिससे कॉटन मिलों के लिए झूम की खेती के जरिए कॉटन का अबाधित प्रवाह बनाए रखा जा सके। बोडो जनजाति के लोग मूलतः भूटान के हैं और बाद में वे असम में आकर बस गए। टोटोपारा इलाके के टोटो जनजाति के लोग भूटान से आकर उत्तर बंगाल की सीमा पर आकर बस गए। इनमें अनेक ऐसी जनजातियां भी हैं जो एक जमाने में अपराधी जाति के रूप में ही जानी जाती थीं उन्हें भूटान के राजा ने अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था। मेघालय में रहने वाली खासी जनजाति के लोग मूलतः कम्पूचिया के हैं और माइग्रेट होकर कुछ सौ वर्ष पहले ही मेघालय में आकर बसे हैं। ये खमेर जनजाति का अंग हैं। देंजोंग भूटिया जनजाति जो सिक्किम की वफादार जनजाति है, वह तिब्बत से आकर बसे हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल के वीरभूम और मिदनापुर जिले से माइग्रेट करके संथाल जनजाति के लोग झाररखण्ड के संथाल परगना में जाकर बस गए हैं। ये ऐतिहासिक तथ्य हैं। लेकिन इस ऐतिहासिक तथ्य से मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं छीन जाता। जब तक जंगल तथाकथित सभी लोगो को डराता रहा तब तक उसमे निवास करने वाले आदिवासी सुरक्षित थे। प्रकृति की गोद में अलमस्त सी जिन्दगी से इन्हें कोई शिकवा शिकायत भी नहीं थी। लेकिन पैसे की भूख तथाकथित सभ्य मानव को जंगल तक खींच लाई और आदिवासी जंगल से बेदखल किये जाने लगे। सरकार के पास इनके पुनर्वास की कोई योजना नहीं है। अपने जल-जंगल-जमीन से बेदखल महानगरों में शोषित-उपेक्षित आदिवासी किस आधार पर इसे अपना देश कहें बाजार और सत्ता के गठजोड़ ने आदिवासियों के सामने अस्तित्व की चुनौती खड़ी कर दी है। जो लोग आदिवासी इलाकों में बच गए ,वे सरकार और उग्र वामपंथ की दोहरी हिंसा में फंसे हैं। अन्यत्र बसे आदिवासियों की स्थिति बिना जड़ के पेड़ जैसी हो गई है। नदियों, पहाड़ों, जंगलों, आदिवासी पड़ोस के बिना उनकी भाषा और संस्कृति, और उससे निर्मित होने वाली पहचान ही कहीं खोती जा रही है। आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व के लिए इतना गहरा संकट इससे पहले नहीं पैदा हुआ। जब सवाल अस्तित्व का हो तो प्रतिरोध भी स्वाभाविक है। इस प्रतिरोध को भुनाने की कोशिश नक्सलवाद के रूप में नजर आती है। इन्हें सर्वप्रथम यही नहीं मालूम कि नस्क्सल पंथ है क्या भोले-भाले आदिवासी सरकार और नक्सलवादी दोनों ओर से पिस रहे हैं। आज जरुरत है एक मानवीय सोच की,या तो इन्हें इनका इलाका फिर से वापस मिल जाए ताकि तथाकथित सभ्य समाज के प्रपंचो से दूर ये अपनी संस्कृति के मौलिक स्वरूप के साथ जीवन यापन कर सके या फिर समाज के मुख्यधारा में जोड़ने की कोशिश हो ताकि शहरों में आकर ये जंगली ना कहलायें। (लेखक- संजय गोस्वामी/ ईएमएस)

हैदराबाद का विलयः मुक्ति या राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर यात्रा?

सत्रह सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ। हालांकि हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाने की कार्यवाही को पुलिस एक्शन कहा जाता है लेकिन वास्तव में यह काम भारतीय सेना ने किया था। इसे आपरेशन पोलो का नाम दिया गया था और इसे जनरल चौधरी के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। इसकी याद में भाजपा इस दिन को हैदराबाद मुक्ति दिवस के नाम से मनाती है, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार इसे प्रजा पालन दिवस (लोकतंत्र के आगाज़ के दिन) के रूप में याद करती है। भाजपा नेता किशन रेड्डी ने कहा है कि इसे हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में न मनाना उन लोगों का अपमान है जिन्होंने सैन्य कार्यवाही के जरिए हुए हैदरबाद के विलय के संघर्ष में अपने जीवन का बलिदान दिया था।

कुछ अन्य लोग कहते हैं कि नेहरू और पटेल के इस्लामोफोबिया के चलते हैदराबाद को बलपूर्वक भारत में शामिल किया गया। इनमें से अधिकांश बातें या तो एकपक्षीय हैं या पूर्वाग्रहपूर्ण हैं। क्या एक मुस्लिम शासक वाली रियासत को मुस्लिम राज्य (हैदराबाद) कहना उचित है, जबकि वहां हिंदुओं का बहुमत था। इसी तरह, क्या मुस्लिम-बहुल और हिंदू शासक वाले राज्य (कश्मीर) को हिंदू रियासत कहना ठीक होगा?

हालांकि कई अध्येता हैदराबाद और कश्मीर के भारत के विलय को धार्मिक नज़रिए से देखते हैं। लेकिन इसकी मुख्य वजहों में से एक थी भौगोलिक और दूसरी थी राजशाही से लोकतंत्र की ओर यात्रा। कश्मीर में यह किस हद तक हासिल किया जा सका, यह शंकास्पद है क्योंकि इस इलाके में पड़ोसी पाकिस्तान की दखलअंदाजी एक बड़ा मुद्दा है। पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता था और मानता था कि मुस्लिम-बहुल होने के कारण कश्मीर का विलय जिन्ना के 'द्विराष्ट्र सिद्वांत' के अनुरूप पाकिस्तान में होना चाहिए। द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रतिपादक सावरकर थे।

तो फिर आखिर क्यों नेहरू ने कश्मीर को भारत में शामिल करवाने में रूचि दिखाई? क्या इसके पीछे सिर्फ भौगोलिक विस्तारवाद था या इसका उद्देश्य सामंतवाद और राजशाही के खिलाफ वहां चल रहे लोकतांत्रिक आंदोलन का समर्थन करना था? शेख अब्दुल्ला ने अपने लोकतांत्रिक नजरिए के चलते अपनी मुस्लिम कान्फ्रेंस का नाम बदलकर नेशनल कान्फ्रेंस किया। वे धर्मनिरपेक्षता के पैरोकार थे और गाँधी और नेहरु के धर्मनिरपेक्ष-लोकतान्त्रिक मूल्यों के समर्थक थे। पाकिस्तानी सेना के आक्रमण, जिसे कबायलियों का हमला बताया गया, को पर्दे के पीछे से अमरीका और ब्रिटेन द्वारा शह दिए जाने से समस्या और जटिल हो गई।

इसके अलावा सार्वभौमिकता का मसला भी था। राजा-नवाब और कई अन्य लोग भी रियासतों पर उनके शासकों के धर्म के आधार पर लेबल चस्पा करते थे। भारतीय राष्ट्रवादी मानते थे कि सार्वभौमिकता जनता में निहित होती है न कि शासकों में। हैदराबाद के भारतीय संघ में विलय के जटिल मसले को इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए।

भारत के स्वतंत्र होने पर उस समय मौजूद 600 से अधिक रियासतों को विकल्प दिया गया था कि वे या तो अपनी रियासत का भारत या पाकिस्तान में विलय कर लें, या फिर स्वतंत्र रहें। अंग्रेजी राज में इन रियासतों को कुछ हद तक स्वायत्ता हासिल थी, लेकिन अब उनके सामने असमंजस की स्थिति थी। उनमें से अधिकतरहे शासक आजाद बने रहना चाहते थे। लार्ड माउंटबेटन ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें अपनी रियासत का उस देश में विलय करना चाहिए जो भौगोलिक दृष्टि से उनकी रियासत के निकट हो। ज्यादातर रियासतों का विलय, सरदार पटेल की निगरानी में किआ जा रहा था और माउंटबेटन ने रियासतों के राजाओं-नवाबों को रक्षा, संचार और विदेशी मामलों को छोड़कर ज्यादातर अन्य मामलों में अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्ता देने का वायदा किया था। इसके बदले में उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि वे उनकी अकूत संपत्ति और धन के स्वामी बने रहेंगे। अंततः अधिकांश रियासतों ने भारत का हिस्सा बनने का फैसला किया। त्रावणकोर के हिंदू शासक भी काफी हिचकिचाहट के बाद भारत का हिस्सा बनने के लिए राजी हुए। कश्मीर के राजा हरिसिंह ने अपनी रियासत का भारत में विलय करने से इंकार कर दिया और हैदराबाद के निजाम भी इसके लिए राजी नहीं हुए।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, भारतीय नेता मानते थे कि सार्वभौमिकता राजाओं में नहीं वरन् जनता में निहित है। इन राजाओं में से अधिकांश अंग्रेजों के प्रति वफादार थे और काफी ऐशोआराम की जिंदगी बसर कर रहे थे। जूनागढ़ को सैन्य कार्यवाही के माध्यम से भारत में शामिल किया गया और इसके बाद हुए जनमत संग्रह में जनता ने इस निर्णय की पुष्टि की। हैदरबाद के निजाम के पास प्रचुर संपदा थी और वे या तो स्वतंत्र रहना चाहते थे या अपनी रियासत का पाकिस्तान में विलय करना चाहते थे। पाकिस्तान में विलय के इरादे की वजह धार्मिक न होकर यह थी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी न करने का वायदा किया था।

भारत कई कारणों से हैदराबाद का भारत में विलय करवाने का इच्छुक था। लेकिन इस्लामोफोबिया इसका कारण नहीं था। इसका सबसे प्रमुख कारण था हैदराबाद रियासत की भौगोलिक स्थिति, जो भारत के लगभग मध्य में था॥ चारों ओर से भारत से घिरा एक स्वतंत्र देश या एक ऐसा राज्य जो पाकिस्तान का हिस्सा होता, एक स्थायी समस्या बन जाता। नेहरू-पटेल की नजरों में भी यही बात सबसे महत्वपूर्ण थी। निजाम के साथ नवंबर 1947 में एक स्टैंडस्टिल (यथास्थिति) समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो अंतिम निर्णय होने तक प्रभावी रहता। विचार यह था कि इस समय का उपयोग हैदराबाद के प्रशासन का लोकतांत्रिकरण करने में किया जाए ताकि समझौता वार्ताएं करने में आसानी हो। निजाम ने इस समय का उपयोग रजाकार नामक एक अनियमित सैन्यबल में नई भर्तियाँ कर अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करने में किया, जिसका नेतृत्व अरब मूल के मेजर जनरल एसए ईएल एड्रोस के हाथ में था जो हैदराबाद राज्य के सैन्यबल के कमांडर इन चीफ थे।

इस बीच कांग्रेस ने राज्य के प्रशासन के लोकतात्रीकरण की मांग करते हुए सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। करीब 20,000 सत्याग्रहियों को जेलों में ठूंस दिया गया। राज्य की प्रताड़ना और रजाकारों के अत्याचारों से बचने के लिए कई लोग रियासत छोड़कर भाग गए। कम्युनिस्टों ने भी खेतिहर भूमि के पुनर्वितरण और ज़मींदारों के खिलाफ व रजाकारों के अत्याचारों से जनता की रक्षा करने के लिए दलम् (समूहों) का गठन किया। निजाम समझौता वार्ताओं को लंबा खींचने का प्रयास कर रहे थे और रजाकारों के जुल्म बढ़ते जा रहे थे। निजाम विरोधी संघर्ष को रियासत के कुछ मुसलमानों का और सारे देश के बहुत से मुसलमानों का समर्थन हासिल था।

पटेल ने सुहारवर्दी को लिखा, ''हैदराबाद के सवाल पर भारतीय मुसलमान खुलकर हमारा साथ दे रहे हैं और इसका देश में अच्छा असर हो रहा है''। इस पृष्ठभूमि में सैन्य कार्यवाही प्रारंभ की गई, जिसमें, एक रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 40,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई।

हम इतिहास के वे हिस्से चुन सकते हैं जो हमारी मर्जी का नैरेटिव निर्मित करने में सहायक हो। कई अध्येताओं के नैरेटिव धर्म-केन्द्रित है और वे यह साबित करना चाहते हैं कि हैदराबाद का विलय भारतीय नेतृत्व के इस्लामोफोबिया का नतीजा था। इस पूरे मामले के मुख्य पहलुओं पर विचार करते समय सारी जटिलताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पहला पहलू है भौगोलिक कारण, जो भविष्य की समस्याओं से बचने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। और दूसरा है लोकतांत्रीकरण और जमींदारी प्रथा के खिलाफ कम्युनिस्टों द्वारा गठित स्थानीय दलम। इस मसले पर नेहरू और पटेल की एकपक्षीय और पक्षपातपूर्ण आलोचना के पीछे उनकी छवि बिगड़ने की कोशिश है। (लेखक – राम पुनियानी/ईएमएस) (अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया। लेखक आईआईटी मुंबई में पढ़ाते थे और सन 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं)

अब अदालत में लहसुन की सुनवाई

मुझे आज लेबनान पर हो रहे हमलों पर लिखना था ,लेकिन लिख रहा हूँ लहसुन के बारे मे। हमारे देश की अदालतें इतनी दरियादिल हैं कि वे एक और यदि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता के मामले की सुनवाई करतीं हैं तो दूसरी तरफ लहसुन पर आयी याचिका की सुनवाई भी करतीं हैं और वो भी चीनी लहसुन के मामले की।

लहसुन को हमारे यहाँ लशुन भी कहते है। लहसुन हालाँकि प्याज जाति का कंद है किन्तु प्याज की गाँठ होती है और लहसुन की कलियाँ। अदालत में विवाद उस लहसुन का है जो हमारा नहीं बल्कि चीन का है ,और चीनी लहसुन पर भारत सरकार ने रोक लगा रखी है ,फिर भी चीन का लहसुन भारतीय बाजारों में इफरात में बिक रहा हैमामला दिलचस्प है इसलिए मैंने दूसरे तमाम विषयों को तिलांजलि देकर लहसुन पर लिखा शुरू कर दिया।

प्रतिबंध के बावजूद चीन के खतरनाक लहसुन के धड़ल्ले से देश में आने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा आयुक्त और कलेक्टर को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। फरियादी की ओर से पेश किए गए चीन के लहसुन को प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के पेश हुए अफसर से सील करवा दिया। अदालत ने 15 दिन में इसकी जांच रिपोर्ट मांगी हैइलाहबाद का हाईकोर्ट सचमुच सम्वेदनशील है। हर मामले में संवेदनशील है । राहुल गाँधी की नागरिकता के मामले में भी और चीनी लहसुन की बिक्री के मामले में भी। आपको ये जानकर हैरानी होगी की इलाहबाद हाईकोर्ट में लंबित मामलों की संख्या 10.74 लाख है। देश में 25 हाईकोर्ट में से इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में सबसे आगे है। ये राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के आंकड़े हैं।

बहरहाल लहसुन पर लौटते है। इलाहबाद हाईकोर्ट ने कहा कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त और लखनऊ के डीएम हेल्पलाइन नंबर जारी करें, जिससे लोग चीन के लहसुन की बिक्री की शिकायत उस पर दर्ज करवा सकें। कोर्ट ने इस नंबर पर मिलने वाली शिकायतों पर सख्त करवाई करने के निर्देश दिए हैंन्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर दिया। मोतीलाल ने खतरनाक चीनी लहसुन की बिक्री की प्रकाशित खबरों को याचिका के साथ लगाकर इसपर सख्त प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया था। फरियादी का कहना है की देश में 2014 से ही इस लहसुन की बिक्री प्रतिबंधित है, इसके बावजूद बाजारों में यह खुलेआम बिक रहा है।

लहसुन भले ही हमारे यहां औषधीय माना जाता है लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे हाथ भी नहीं लगाते ,उनके लिए लहसुन अस्पृश्य है । हमारे वैद्य जी कहते हैं कि लहसुन में रासायनिक तौर पर गन्धक की आधिक्य होती है। इसे पीसने पर ऐलिसिन नामक यौगिक प्राप्त होता है जो प्रतिजैविक विशेषताओं से भरा होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, एन्ज़ाइम तथा विटामिन बी, सैपोनिन, फ्लैवोनॉइड आदि पदार्थ पाए जाते हैं।अक्सर लहसुन खली पेट खाने की सलाह दी जाती है। लहसुन को लेकर कहावते उतनी नहीं हैं जितनी प्याज को लेकर है। प्याज को काटा जाता है ,लहसुन को छीला जाता है । लहसुन की पैकेजिंग प्रकृति ने मक्के के भुट्टे की तरह बहुत आकर्षक तरीके से की है। जाहिर है कि ये विशेष कंद है अन्यथा इसे धरती के भीतर आलू की तरह उगने के लिए न छोड़ दिया जाता ?

कहते हैं कि लहसुन एक दक्षिण यूरोप में उगाई जाने वाली प्रसिद्ध फसल है। भारत में लहसुन की खेती को ज्यादातर राज्यों में की जाती है लेकिन इसकी मुख्य रूप से खेती गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में की जाती है। इसका 50 प्रतिशत से भी ज्यादा उत्पादन गुजरात और मध्यप्रदेश राज्यों में किया जाता है। हमारे यहां एग्रीफाउंड वाइट (जी. 41), यमुना वाइट (जी.1), यमुना वाइट (जी.50), जी.51 , जी.282 ,एग्रीफाउंड पार्वती (जी.313) और एच.जी.1 प्रजाति का लहसुन मिलता है ,लेकिन हमारे पड़ौसी देश चीन ने हमारे लहसुन के सामने अपना लहसुन खड़ा कर दिया।

आपको शायद पता हो या न हो लेकिन भारत में साल 2014 से ही प्रतिबंधित किया गया ,लेकिन चाइनीज लहसुन भारतीय मंडियों और खुदरा बाजार में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है. जिस लहसुन को देसी समझकर आप अपने घर ले जा रहे हैं और दाल-सब्जी में तड़का मारकर खा रहे हैं, वह सिंथेटिक रूप से खतरनाक कैमिकल्स से बना फंगस वाला चाइनीज लहसुन हो सकता है। चीनी लहसुन का अवैध व्यापार एक लम्बे अरसे से जारी है। चीन अक्सर नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते इसकी यहां डंपिंग करता है. इन दोनों ही देशों के साथ भारत लहसुन का डयूटी फ्री व्यापार करता है. भारत पहुंचने वाला चीनी लहसुन कई बैक्टीरिया और बीमारियों को साथ लेकर पहुंचता है. ये लोगों की सेहत पर असर डालता है। हाल में एक वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि चीन में लहसुन 'सीवर के पानी' में पैदा होता है. इसे सफेद दिखाने के लिए आर्टिफिशियल तरीके से 'ब्लीच' किया जाता ह।

आपको शायद पता न हो लेकिन हकीकत ये है ज भारत में करीब 32.7 लाख टन लहसुन का उत्पादन होता है. भारत में सबसे ज्यादा लहसुन का उतपादन मध्य प्रदेश में होता है। हालांकि चीन में उत्पादन गिरने के बावजूद वह दुनिया में नंबर-1 है । चीन में हर साल करीब 2 से 2.5 करोड़ टन लहसुन का उत्पादन होता है, चीन के मुकाबले भारत का लहसुन थोड़ा छोटे आकार का होता है। वहीं इसका रेट चीन के मुकाबले काफी कम है। चीनी लहसुन की ग्लोबल मार्केट में 1250 डॉलर प्रति टन कीमत है, तो वहीं भारतीय लहसुन 450 से 1000 डॉलर प्रति टन तक मिलता है। इसलिए भारत गरीब से लेकर अमीर देशों तक के हिसाब से लहसुन की क्वालिटी उपलब्ध करा पाता है। चीनी लहसुन की मांग अधिकतर अमेरिका और यूरोपीय देशों में है, जबकि भारत मलेशिया, थाईलैंड, नेपाल और वियतनाम को लहसुन का बड़े पैमाने पर निर्यात करता है ।

बावजूद इसके भारतीय चमकदार बगुलामुखी रंग की दीवानगी के फेर में पढ़कर चीनी लहसुन खरीद लाते हैं। दुर्भाग्य ये है कि जिस तरह हमारी सरकार चीनी घुसपैठ रोकने में नाकाम है उसी तरह लहसुन की घुसपैठ के मामले में भी नाकाम है । प्रतिबंध के बाद भी भारत में चीनी लहसुन की उपलब्धता इसका प्रमाण है । खुद प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में चीनी लहसुन की घुसपैठ है । गुजरात के लहसुन उत्पादक इसके खिलाफ लामबंद भी हैं। अब जब चीनी लहसुन चुनावी मुद्दा बनेगा, तब शायद इस मामले को सरकार गंभीरता से ले। (लेखक-राकेश अचल/ईएमएस)

शब्द पहेली - 8143

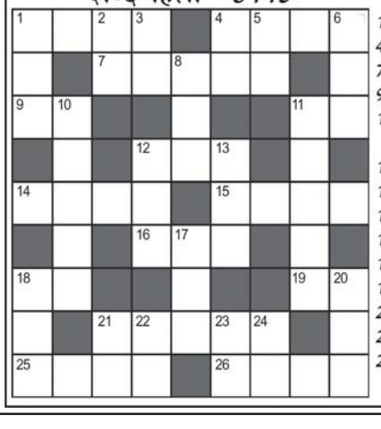

बाएँ से दाएँ

1. आदत, स्वभाव-4
4. सुरक्षित-4
7. जरुरतमंद-5
9. भीगा हुआ-2
11. मक्का-मदीना की यात्रा-2
12. सोना, धतुरा-3
14. धक्का देना-4
15. खानाबदोश, बंजारा-4
16. अंधेरा, अंधकार-3
18. खामी, बुरी आदत-2
19. ईसाई साध्वी-2
21. नायक का विलोम-5
25. करिश्मा, करामात-4
26. महीन व मंहगे कपड़े का एक प्रकार -4

ऊपर से नीचे

1. अंग्रेज, विदेशी-3
2. लीन, मगन-2
3. पैंदा, तला-2
4. रिश्तेदार-2
5. थूक, लेस-2
6. तहजीब, सलीका-3
8. देह, काया-3
10. टोने-टोटकों वाली किताब-5
11. स्वदेशवासी -5
12. कपड़े की दीवार-3
13. अनुमान, आकलन-3
17. राजी करना-3
18. चश्मा-3
20. अनुकृति-3
21. पत्र, चिट्ठी-2
22. होठ, अधर-2
23. मृत्यु देवता, यमराज-2
24. बीता हुआ दिन-2

शब्द पहेली -8142 का हल

■	त	ल	ब	■	ट	म	ट	म
प	■	■	ट	स्त	क	■	■	हा
र	■	ना	नौ	■	ला	श	■	ज
ख	ल	ना	य	क	■	ब	त	न
■	ल	■	त	■	ना	■	री	■
म	ना	ही	■	ह	क	ब	का	ना
हा	■	ना	क	■	क	ल	■	पि
ब	■	■	स	पा	ट	■	■	का
त	ब	वा	र	■	ना	ह	क	■

Jagrutidaur.com, Bangalore

खेल - समाच

एनएसई और बीएसई ने ट्रांजेक्शन फीस में किया बदलाव

-1 अक्टूबर से कैश, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रांजैक्शन के ट्रेड में लागू होंगी नई दरें

मुंबई(ईएमएस)।नेशनलस्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई)ने कैश और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड के लिए लगने वाली ट्रांजैक्शन फीसमेंबदलाव किया है। एनएसई में कैश मार्केट के लिए अब ट्रांजैक्शन फीस 2.97 रुपए/लाख ट्रेडेड वैल्यू होगी। वहीं इक्विटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में फ्यूचर्स में ट्रांजैक्शन फीस 1.73 रुपए/लाख ट्रेडेड वैल्यू होगी।

जबकि ऑप्शंस में 35.03 रुपए/लाख प्रीमियम वैल्यू होगी। करेंसी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में एनएसई ने फ्यूचर्स के लिए ट्रांजैक्शन फीस 0.35 रुपए/लाख ट्रेडेट वैल्यू रखी है। जबकि करेंसी ऑप्शंस और इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस में यह फीस31.1रुपए/लाख प्रीमियम वैल्यू होगी। इसी तरह बीएसई ने भी अपनी ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव किया है। करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स (क्रॉस करेंसी फ्यूचर्स के साथ)पर एक करोड़ की टर्नओवर वैल्यू पर 45रुपए फीस लगेगी। बीएसई के ऑप्शंसपरएककरोड़ की प्रीमियम टर्नओवर वैल्यू पर100 रुपए की फीस लगेगी। येबदलाव1 अक्टूबर से लागू होंगे। एनएसई और बीएसई ने ट्रांजैक्शन फीस में यह बदलाव मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) की ओर से जुलाई में आए मैंडेट के बाद किए हैं। उस मैंडेट में सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजेज को मार्केट इंफ्रास्ट्रक्टर इंस्टीटयूशंस के सभी सदस्यों के लिए यूनिफॉर्म फ्लैट फी स्ट्रक्चर रखना जरूरी किया था। इसके जरिए सेबी वॉल्यूम और एक्टिविटी के आधार पर अलग-अलग स्लैबों में अलग-अलग फीस के स्ट्रक्चर को बदलना चाहती है।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार जल्द होगा 700 अरब डॉलर के पार

- लगातार 6वें सप्ताह फॉरेक्स रिजर्व में करीब 22 अरब डॉलर की हुई बढ़ोतरी

नई दिल्ली (ईएमएस)। घरेलू शेयर बाजार लगातार इतिहास रचता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशी बाजारों में भी भारत के सेंसेक्स और निफ्टी की चर्चा हो रही है। वहीं भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार इतिहास रचता हुआ दिखाई दे रहा है। जानकारों की मानें तो आने वाले कुछ हफ्तों देश का फॉरेक्स रिजर्व 700 अरब डॉलर के भी पार सकता है। वैसे फॉरेक्स रिजर्व में लगातार 6वें हफ्ते इजाफा देखने को मिला है। इस दौरान फॉरेक्स रिजर्व में करीब 22 अरब डॉलर की बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 20 सितंबर को समाप्त सप्ताह में 2.84 अरब डॉलर बढ़कर 692.30 अरब डॉलर के नये सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। इससे पिछले सप्ताह देश का विदेशी मुद्रा भंडार 22.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 689.46 अरब डॉलर की नयी ऊंचाई पर जा पहुंचा था। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के जारी आंकड़ों के अनुसार 20 सितंबर को समाप्त सप्ताह में मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां 2.06 अरब डॉलर बढ़कर 605.69 अरब डॉलर हो गई। दूसरी ओर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 20 सितंबर को समाप्त सप्ताह में मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां 2.06 अरब डॉलर बढ़कर 605.69 अरब डॉलर हो गई।

डॉलर के संदर्भ में उल्लेखित विदेशी मुद्रा आस्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं की घट-बढ़ का प्रभाव शामिल होता है। समीक्षाधीन सप्ताह में स्वर्ण भंडार का मूल्य 72.6 करोड़ डॉलर बढ़कर 63.61 अरब डॉलर रहा। विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 12.1 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.54 अरब डॉलर हो गया। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार आलोच्य सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के पास भारत का आरक्षित भंडार 6.6 करोड़ डॉलर घटकर 4.46 अरब डॉलर रहा।

भारत और भूटान ने बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने का निर्णय लिया

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत और भूटान ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कुछ सीमा पार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास में तेजी लाने के लिए चर्चा की। इनमें अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एक एकीकृत जांच चौकी की स्थापना का मुद्दा भी शामिल रहा। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल और भूटान के उद्योग, वाणिज्य एवं रोजगार मंत्रालय (एमओआईसीई) के सचिव दाशो ताशी वांगमो के बीच थिम्पू में हाल ही में हुई बैठक में इन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उन्होंने बैठक की सह-अध्यक्षता करते हुए सीमापार और संपर्क के बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने का निर्णय लिया। इसमें जयगांव-फुंटशोलिंग में एक एकीकृत जांच चौकी की स्थापना और कोकराझार-गेलेफू और बानरहाट-समात्से के बीच रेल संपर्क शामिल है। बयान के अनुसार दोनों सचिवों ने भूटान से भारत में कबाड़ के आयात के लिए एलसीएस (भूमि सीमा शुल्क स्टेशन) जयगांव की अधिसूचना, भारत-भूटान सीमा पर सीमा हाट की स्थापना, व्यापारियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने और भूटान से भारत में बोल्डर के आयात पर विचार-विमर्श किया। इसके अलावा भूटान से भारत में आयात के लिए लकड़ी की तीन अतिरिक्त किस्मों को शामिल करने पर भी चर्चा हुई।

इस साल आईपीओ बाजार रहेगा तेज

-दिसंबर तक 1 लाख करोड़ जुटा सकती हैं कंपनियां

मुंबई (ईएमएस)। इस साल का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) बाजार में भी शेयर बाजार की तरह तेजी बनी रहने का अनुमान है। बताया जा रहा है कि कंपनियां दिसंबर तक एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जुटा सकती हैं। इससे पहले 2021 में 63 आईपीओ के जरिए 1.20 लाख करोड़ रुपए जुटाने का रिकॉर्ड बनाया था।

इस साल के अंत तक कई बड़ी कंपनियां आईपीओ लेकर आ रही हैं। एक्सचेंजों के आंकड़ों के अनुसार इस साल अब तक कुल 62 आईपीओ आए हैं, जिन्होंने 64,513 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसके मुकाबले 2023 में 57 कंपनियों ने 49,437 करोड़ और 2022 में 40 कंपनियों ने 59,939 करोड़ रुपए जुटाए थे। सितंबर में 10 आईपीओ के जरिये 11,826 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, और दो और कंपनियां 500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बाजार में उतरने वाली हैं। इस साल के अंत तक कई बड़ी कंपनियां आईपीओ लेकर आ रही हैं, जिससे बाजार और गर्म हो सकता है। ह्यूंडई मोटर 25,000 करोड़ रुपए के सबसे बड़े इश्यू के साथ अक्टूबर के अंत या नवंबर के पहले सप्ताह में आ सकती है। स्विगी 11,000 करोड़ रुपए के आईपीओ के साथ नवंबर में बाजार में उतरने की तैयारी में है।

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 10,000 करोड़ रुपए और अफकॉन्स इन्फ्रा 8,400 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही हैं। ये चार कंपनियां मिलकर 54,000 करोड़ रुपए जुटा सकती हैं। इसके अलावा वॉरी एनर्जी 3,000 करोड़ और वन मोबिक्विक 700 करोड़ रुपए जुटाने के लिए अक्टूबर में बाजार में आएंगे।

ब्रिटेन का भी मिला साथ, तो यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता पक्की!

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत काफी समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में स्थायी सदस्यता मांग कर रहा है, लेकिन चीन द्वारा लगाई गई कुछ रोक की वजह से मांग पूरी होने में ?दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हाल में भारत के समर्थन में कई बड़े देशों का रुख सकारात्मक हुआ है। अमेरिका और फ्रांस के बाद अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने भी भारत की यूएनएससी में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में अपने संबोधन के दौरान यह विचार व्यक्त किया। स्टार्मर ने कहा कि यूएनएससी को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और कार्रवाई करने के लिए तैयार निकाय के रूप में बदलने की जरूरत है। उन्होंने भारत, जापान, ब्राजील, और जर्मनी को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया, साथ ही अफ्रीका को भी स्थायी प्रतिनिधित्व दिए जाने की वकालत की। इसके अलावा उन्होंने निर्वाचित सदस्यों के लिए अधिक सीटें बढ़ाने की भी आवश्यकता बताई। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने भी भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन में बयान दिए थे। मैक्रॉन ने यूएनएससी में सुधार और इसे अधिक समावेशी बनाने पर जोर दिया था। उन्होंने भारत, ब्राजील, जापान, और जर्मनी के साथ दो अफ्रीकी देशों को भी स्थायी सदस्यता देने की वकालत की। भारत का तर्क है कि 1945 में स्थापित 15 सदस्यीय यूएनएससी मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता और इस मंच में सुधार की आवश्यकता है। भारत के अलावा जापान, ब्राजील, और जर्मनी भी लंबे समय से सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं, जिसे जी4 देशों का समूह कहा जाता है। भारत का कहना है कि उसे इस महत्वपूर्ण मंच पर स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि वह दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और आर्थिक शक्तियों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के योगदान और विकासशील देशों के मुद्दों पर उसकी मजबूत स्थिति इसे इस सदस्यता का मजबूत दावेदार बनाती है।

महिलाओं को वजनदार मंगलसूत्र खरीदने में अब नहीं होगी समस्याः गोयल

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सोना सस्ता होने के बाद महिलाएं अब अधिक वजनदार मंगलसूत्र भी खरीद सकती हैं। उन्होंने कहा ?कि मुझे बताया गया है कि आयात शुल्क में कटौती के बाद कारोबार में उछाल आया है। अब मेरी राय में हमारी बहनों को अपने मंगलसूत्र खरीदने में मामले में कोई समस्या नहीं होगी और आप वजनदार मंगलसूत्र भी खरीद सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने के आयात पर सीमा शुल्क में भारी कटौती की घोषणा की थी। इस तरह शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत कर दिया गया है। गोयल ने कहा कि स्वर्ण उद्योग में शुल्क कम करने की बात हर चर्चा में छाई रहती थी और शुल्क कम करने की मांग होती रही थी। उन्होंने स्वर्ण एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद से विदेशों में आभूषण विक्रेताओं की दुकानों से भारतीय पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने में मदद करने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे देश और पूरे क्षेत्र को मदद मिलेगी।

जीएसटी के दायरे में आएंगे पेट्रोल-डीजल, 20 रुपए होगा सस्ताः पुरी

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल को वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने की संभावना पर चर्चा की। पुरी ने कहा कि यह कदम देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जरूरी है और इसके लिए आम सहमति बनानी होगी। अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमत में 20 रुपए लीटर तक की कमी देखने को मिल सकती है। पुरी ने पुणे इंटरनेशनल सेंटर के 14वें स्थापना दिवस पर एक व्याख्यान में कहा कि वह लंबे समय से इस मुद्दे का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी वरिष्ठ सहयोगी, वित्त मंत्री, ने भी इस दिशा में सकारात्मक बातें की हैं। मंत्री ने कहा कि पेट्रोल और डीजल राज्यों के लिए महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत हैं और इसलिए सभी राज्यों की सहमति आवश्यक होगी। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ईंधन की खोज और उत्पादन को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि अगले दो दशकों में भारत दुनिया की कुल ऊर्जा खपत में 25 प्रतिशत का योगदान देगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पेट्रोल और डीजल राज्यों के लिए महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी राज्यों की सहमति की आवश्यकता है। हालांकि, उन्होंने कहा कि सभी राज्यों का इसमें शामिल होना कठिन है, क्योंकि शराब और ऊर्जा जैसे उत्पादों पर राज्य करों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। पुरी ने केरल हाईकोर्ट के उस सुझाव का भी उल्लेख किया, जिसमें जीएसटी परिषद में इस मुद्दे पर चर्चा करने की बात कही गई थी। लेकिन केरल के वित्त मंत्री ने इससे असहमति जताई, क्योंकि गैर-भाजपा शासित राज्य पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला अतिरिक्त वैट छोड़ने को तैयार नहीं हैं। इस स्थिति में, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए सहमति स्थापित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, लेकिन यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

बाइडेन की नाक के नीचे भारत-रुस की सीक्रेट बैठक.....अमेरिका टेंशन में

वाशिंगटन (ईएमएस)। संयुक्त राष्ट्र में दुनियाभर के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस, चीन, अमेरिका, भारत और यूरोप के एक से बढ़कर एक देश और उनके प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। इस बीच कुछ ऐसी मुलाकात हो रही है, जिसे लेकर अमेरिका का बीपी हाई हो गया है। उसमें एक मुलाकात जहां ब्रिक्स देशों की थी। वहीं दूसरी मुलाकात चीन और पाकिस्तान के लिए खलबली पैदा करने वाली थी। ये मुलाकात भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गोई लावरेव के बीच हुई। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस का दौरा किया और फिर बाद में व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। फिर उनका अगला दौरा अमेरिका में निर्धारित हुआ। अमेरिका में जो बाइडेन के साथ उनकी युद्ध को लेकर बात हुई। अब जयशंकर और लावरोव मिले हैं।

मुलाकात में लावरोव और जयशंकर आमने सामने थे। ब्रिक्स के विस्तार को लेकर जब हर तरफ चर्चा हो रही है। फिर दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत शुरू हो गई। बातचीत के दौरान यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जिक्र हुआ। साथ ही ब्रिक्स को लेकर होने वाली बैठक का भी जिक्र हुआ। एशिया पेसेफिक रिजन को जोड़ने के लिए पश्चिमी देश किस तरह नाटो का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर बार रूस जोर देता आया है। रूस ने बताया कि दोनों देशों के बीच आपसी साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। दोनों ने कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी चर्चा की। इसके पहले 25 सितंबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) को बताया कि उन्होंने रूस के साथ कीव के लंबे युद्ध को समाप्त करने के लिए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत को पहले ही आमंत्रित किया है। ज़ेलेंस्की ने इस बात पर ज़ोर दिया कि एकता हमेशा शांति के लिए काम करती है और युद्ध को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए सभी देशों से सामूहिक तैयारी का आह्वान किया।

मालदीव की चीन से नहीं बैठी पटरी, वापस भारत की शरण में आ रहे मुइज्जू

माले(ईएमएस)। मालदीव ने सोचा था चीन से दोस्ती करके भारत पर दबाव बना लेगा ये उसकी गलत फहमी निकली। अततः मालदीव की सभी गलत फहमियां दूर हो गई और उसे वापस भारत की शरण में लौटना पड़ रहा है। ये इसलिए कहा जा रहा है कि खुद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने इंडिया आउट के किसी भी एजेंडे से इनकार करते हुए कहा कि उनके देश में विदेशी सेना की उपस्थिति द्वीपीय देश के लिए एक गंभीर समस्या थी। अब मुइज्जू अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में भारत की यात्रा करने वाले हैं। उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों में आई कड़वाहट को दूर करने की कोशिश के तौर देखा जा रहा है। वे 6-10 अक्टूबर के दौरान द्विपक्षीय यात्रा के लिए भारत में रहेंगे। नाम नहीं बताने की शर्त पर दोनों देशों के लोगों ने बताया कि पीएम मोदी के साथ उनकी बैठकें 7 अक्टूबर को होने की संभावना है। बता दें कि मुइज़ू पिछली बार 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए छह अन्य क्षेत्रीय देशों के नेताओं के साथ नई दिल्ली आए थे।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में शामिल होने के लिए अमेरिका पहुंचे मुइज्जू ने गुरुवार को प्रिंसटन विश्वविद्यालय के कार्यक्रम 'डीन्स लीडरशिप सीरीज' में एक सवाल के जवाब में यह टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि हम किसी भी समय, किसी भी देश के खिलाफ कभी नहीं रहे। यह भारत को बाहर करना नहीं है। मालदीव के लोगों को अपने देश में विदेशी सेना की उपस्थिति से एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा था। मुइज्जू ने कहा कि मालदीव के लोग नहीं चाहते कि एक भी विदेशी सैनिक देश में रहे।भारत और मालदीव के बीच संबंध पिछले साल नवंबर से ही तनावपूर्ण हो गए थे, जब चीन के प्रति झुकाव रखने वाले मुइज्जू ने मालदीव के राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। मुइज्जू ने भारत से कहा था कि वह देश द्वारा उपहार में दिए गए तीन विमानन प्लेटफॉर्म का संचालन कर रहे लगभग 90 भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुला ले। भारत ने 10 मई तक अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया और उनकी जगह डोर्नियर विमान और दो हेलीकॉप्टरों के संचालन के लिए असैन्य कर्मियों को तैनात कर दिया।

बीआईटी संधि का लाभ उठाए दोनों देशों के कारोबारी : सीतारमण

समरकंद (ईएमएस)। मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत और उज्बेकिस्तान के बीच शनिवार को हुए द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) का दोनों देशों के उद्योग से लाभ उठाने की अपील की है। वित्त मंत्री सीतारमण और उज़्बेकिस्तान के उप प्रधान मंत्री खोदजायेव जमशेद अब्दुखाकिमोविच ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर हस्ताक्षर किए। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच बीआईटी प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय मिसालों और प्रथाओं के आलोक में भारत में उज्बेकिस्तान के निवेशकों और उज्बेकिस्तान में भारतीय निवेशकों को उचित सुरक्षा का आश्वासन देता है। यह न्यूनतम मानक उपचार और गैर-भेदभाव सुनिश्चित करके निवेशकों की धारणा और उनका विश्वास बढ़ाएगा, साथ ही मध्यस्थता के माध्यम से विवाद निपटान के लिए एक स्वतंत्र मंच प्रदान करेगा।

संधिपरहस्ताक्षर कर श्रीमती सीतारमण ने कहादोनों देशों के उद्योगों के बीच सार्थकबातचीत और सहयोग को प्रोत्साहित किया। दोनों पक्षों के कारोबारी समुदायों से बीआईटी का लाभ उठाने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि यह निवेश संबंधों को एक नए पथ पर ले जाएगा।

उन्होंने कहा कि नई बीआईटी आधुनिक अंतरराष्ट्रीय निवेश मानकों पर आधारित है, दोनों पक्षों के निवेशकों को मजबूत सुरक्षा प्रदान करती है, विश्वास और विश्वास का माहौल बनाती है। इस संधि पर हस्ताक्षर करने से विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर खुलने है।

बीआईटी निवेशों को जब्ती से सुरक्षा प्रदान करता है, पारदर्शिता, हस्तांतरण और नुकसान के लिए मुआवजे का प्रावधान करता है। हालांकि, इस तरह के निवेशक और निवेश संरक्षण प्रदान करते समय, दोनों देशों के विनियमन के अधिकार के संबंध में संतुलन बनाए रखा गया है और इस तरह पर्याप्त नीतिगत स्थान प्रदान किया गया है।

मंदी की मार से जूझता अमेरिका

- बड़ी संख्या में दिवालिया हो रहीं कंपनियां, बंद हो रहे रिटेल स्टोर्स

न्यूयॉर्क,(ईएमएस): अमेरिका में आर्थिक मंदी का गहरा असर रिटेल सेक्टर और कंपनियों पर पड़ा है। कमजोर ग्रोथ रेट और बढ़ती लागत के चलते, 2024 के पहले आठ महीनों में 452 कंपनियां दिवालिया घोषित हो चुकी हैं। इससे पहले 2020 में, कोरोना महामारी के दौरान, इसी अवधि में 466 कंपनियां दिवालिया घोषित की गई थीं। आर्थिक संकट की स्थिति ने न केवल कंपनियों को झकझोर कर रख दिया बल्कि रिटेल सेक्टर को भी बड़ा सदमा दिया है, जिससे स्टोर्स तेजी से बंद हो रहे हैं।

जानकारी अनुसार मंदी का रिटेल स्टोर्स पर गहरा असर देखने को मिला है। वर्ष 2024 में अब तक 4,548 रिटेल स्टोर्स का शटर डाउन हो चुका है, जो पिछले कुछ वर्षों में सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं, नए स्टोर्स की संख्या 4,426 ही है, जो बंद हुए स्टोर्स के आंकड़ों से काफी कम है। साल 2020 के बाद यह पहली बार हुआ कि बंद होने वाले स्टोर्स की संख्या नए खोले गए स्टोर्स से अधिक हो गई है। इस गिरावट का मुख्य कारण महंगाई, बेरोजगारी और मकान व फर्नीचर से संबंधित सामान बेचने वाले विक्रेताओं को हो रहा भारी नुकसान बताया जा रहा है।

बंद हो रहे स्टोर्स

अनेक प्रमुख रिटेल कंपनियों ने भी अपने स्टोर्स बंद करने का फैसला लिया है। डॉलर ट्री ने 1,000 स्टोर्स बंद किए हैं, जबकि फैमिली डॉलर ने 600, सीवीएस ने 900, फुटलॉकर ने 400, और बेस्ट बाइ ने 100 स्टोर्स बंद कर दिए हैं। इसके अलावा, वालग्रीन्स ने 150, एक्सप्रेस ने 95, और वालमार्ट ने 7 स्टोर्स का शटर डाउन किया है। इन स्टोर्स के बंद होने का असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर भी पड़ा है, जो पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उन्हें अब वस्तुओं के और ज्यादा दाम देने पड़ रहे हैं। नए खोले गए स्टोर्स और बंद हुए स्टोर्स की वर्षवार संख्या इस प्रकार है-

नए और बंद स्टोर्स की संख्या

वर्ष	नए खुले	बंद हुए
2020	3,704	9,698
2021	5,048	5,228
2022	5,394	3,819
2023	5,843	548
2024	4,426	4,548

(साल 2024 के आंकड़े माह जनवरी से अगस्त तक के हैं)

ये कंपनियां हो रहीं दिवालिया

एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में जनवरी से अगस्त तक 452 कंपनियों ने दिवालिया प्रक्रिया के लिए आवेदन दिया है। साल 2020 के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पता चलता है कि कंपनियां अपनी परिचालन लागत में हो रही वृद्धि और घटते मुनाफे के कारण अपने अस्तित्व को बचाने में असमर्थ हो गईं हैं। अमेरिका में यह आर्थिक संकट गहराता जा रहा है और आने वाले समय में इसके और भी गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

सूडान के एल फशर में आरएसएफ के हमले में आठ की मौत, 95 घायल

खार्तूम,(ईएमएस)। पश्चिमी सूडान के उत्तरी दारफुर राज्य की राजधानी एल फशर में अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) के हमले में करीब आठ लोगों की मौत हो गई और 95 घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट में स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक इब्राहिम खातिर ने बताया कि आरएसएफ की गोलाबारी का लक्ष्य सूक अल-मवाशी बाजार था, जहां लोगों की भीड़ रहती है। आरएसएफ ने अभी तक इस हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

बता दें 10 मई से एल फशर में सूडानी सशस्त्र बलों (एसएएफ) और आरएसएफ के बीच भीषण झड़पें हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक एल फशर में करीब 15 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से आठ लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हैं। ज्ञात हो कि 22 सितंबर को एसएएफ और आरएसएफ के बीच सशस्त्र संघर्ष में तीन बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई थी और 17 घायल हो गए थे। यह झड़पें पश्चिमी उत्तर दारफुर राज्य की राजधानी एल फशर में हुई थी।

रिपोर्ट के मुताबिक गैर-सरकारी सूडानी डॉक्टर्स नेटवर्क ने एक बयान में चेतावनी दी थी गई कि घनी आबादी वाले शहर में 10 मई से जारी संघर्षों से गंभीर मानवीय आपदा पैदा हो सकती हैं। उन्होंने गोलाबारी तत्काल बंद करने और शहर से नाकाबंदी हटाने की मांग की थी। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक 15 अप्रैल 2023 से सूडान एसएएफ और आरएसएफ के बीच हिंसक संघर्ष में उलझा हुआ है। इस संघर्ष की वजह से करीब 20 हजार लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों घायल हुए हैं। इसके अलावा लाखों लोग विस्थापित हुए हैं।

नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में लहराए दो मैप.....एक का संबंध भारत से

ईरान को चेतावनी, ऐसी कोई जगह नहीं जहां इजराइल नहीं पहुंच सकता

न्यूयॉर्क (ईएमएस)। गाजा युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र में अपने पहले संबोधन में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मध्य पूर्व में संघर्ष के लिए ईरान को मुख्य किरदार के रूप में चित्रित किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान दो मैप प्रदर्शित किए, जिसमें देशों के एक समूह को अभिशाप और दूसरे समूह को आशीर्वाद के रूप में दिखाया गया। उनकी तस्वीर इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है।

दिलचस्प यह है कि दोनों मानचित्रों में फिलिस्तीनी क्षेत्रों- वेस्ट बैंक और गाजा को इजरायल के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। वायरल तस्वीर में नेतन्याहू के दाहिने हाथ के नक्शे में ईरान, इराक, सीरिया और यमन को काले रंग में दिखाया गया है और उन्हें अभिशाप यानी द कर्स करार दिया गया है। जबकि बाएं हाथ के मानचित्र में मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और भारत को हरे रंग में चित्रित किया गया है और इन देशों को आशीर्वाद यानी द ब्लेसिंग बताया गया है।

नेतन्याहू द्वारा दिखाए गए मैप में सीरिया के गोलान हाइट्स क्षेत्र को भी इजरायल का हिस्सा दिखाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रॉप्स का उपयोग करने का इतिहास रखने वाले नेतन्याहू के इस कदम को पड़ोसी अरब देशों के साथ अपने बढ़ते संबंधों पर जोर देने के इजरायल के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर, 2024 को इजरायल पर हमास के हमले की निंदा करने वाले पहले वैश्विक नेताओं में से एक थे। हालांकि, भारत ने क्षेत्र में पूर्ण युद्धविराम का आह्वान किया है और इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष के स्थायी समाधान लिए टू स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया है।

नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में द कर्स और द ब्लेसिंग वाले मैप लहराते हुए कहा कि दुनिया को आशीर्वाद और अभिशाप के बीच चयन करना चाहिए। नेतन्याहू ने ईरान पर निशाना साधा और उस पर चरमपंथी संगठनों को हथियार व मदद देने का आरोप लगाया। उन्होंने दुनिया से इसतरह के देशों का तुष्टिकरण बंद करने का आग्रह किया। नेतन्याहू ने कहा, तेहरान के लिए मेरा एक संदेश है, अगर तुम हम पर हमला करते हो, तब हम तुम पर हमला करेंगे। ईरान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इजरायल न पहुंच सके, और यह पूरे मध्य पूर्व के लिए सच है।

इजरायल द्वारा लेबनान में हिज्बुल्लाह के गढ़ों पर भारी बमबारी के साथ मध्य पूर्व संकट गहरा गया है। नेतन्याहू ने साफ शब्दों में फिलिस्तीन को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इजरायल दुनिया में शांति चाहता है। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा, फिलिस्तीनियों को यहूदियों के प्रति घृणा फैलाना बंद करना चाहिए और इजरायल के साथ समझौता करना चाहिए। इस साल जुलाई में ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के पॉलिटिकल विंग के प्रमुख इस्माइल हनियेह की हत्या के बाद से इजरायल और उसके कट्टर प्रतिद्वंद्वी ईरान के बीच खुले संघर्ष का खतरा बढ़ रहा है।

चीन में हुआ घिनौना हादसा.....सड़कों पर फैल गया मानव मल

बीजिंग (ईएमएस)। चीन के नैनिंग शहर में एक बेहद अजीब और घिनौना हादसा हुआ। जब एक नया इंस्टाल किया गया सीवेज पाइप प्रेशर टेस्ट के दौरान फट गया। इस दुर्घटना ने मानव मल को 33 फुट ऊपर हवा में उछाल दिया, जिससे सड़क पर चलने वाले लोग, कारें और बाइक चालक बुरी तरह प्रभावित हुए।

घटना का वीडियो फुटेज डैशकैम पर कैद हुआ, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से मल का फव्वारा सड़क पर गिरा। विस्फोट की तीव्रता इतनी थी कि एक कार का शीशा करीब टूट गया। इसके अलावा, बाइक चालक और पैदल यात्री बदबूदार स्थिति से गुजरने के लिए मजबूर हो गए। अच्छी बात यह रही कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है। नानिंग म्यूनिसिपल इमरजेंसी मैनेजमेंट ब्यूरो ने पूप वोल्केनो नामक घटना की पुष्टि की है, जो सेप्टिक टैंक के पाइप के फटने के परिणामस्वरूप हुई। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने घटना पर प्रतिक्रिया देकर लिखा, मैं इस वीडियो में बदबू महसूस कर सकता हूं, और कुछ ने मजाक में कहा, बेहद खराब स्थिति में फंस गया हूं। यह घटना एक गंभीर समस्या को उजागर करती है, जिससे सार्वजनिक स्वास

वडोदरा निगम में भर्ती प्रक्रिया में वाला दावा नीतिः राजस्व अधिकारी के बाद अब इंजीनियरों की भर्ती पर विवाद

वडोदरा,28 सितंबर,

वडोदरा नगर निगम में भी भर्ती नियमों में वाला दावा की नीति है। हाल ही में राजस्व अधिकारी के लिए लंबित विभागीय, सतर्कता जांच के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इंजीनियरों की भर्ती प्रक्रिया में इस नियम का पालन नहीं किये जाने के विवाद के बाद अब निगम में कार्यपालक अभियंता (इलेक्ट्रिकल) की सीधी भर्ती की घोषणा से एक और विवाद खड़ा हो गया है. वर्षों से कार्यपालक अभियंता का प्रभार संभाल रहे तीन अभियंताओं द्वारा नगर आयुक्त को पत्र भेजकर कार्यपालक अभियंता विद्युत पद के लिए होने वाली परीक्षा को रद्द करने की मांग की गयी है.

निगम में प्रभारी तीन कार्यकारी अभियंता इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ने मनपा आयुक्त को लिखे पत्र में बताया है कि वडोदरा निगम में अब तक पारित विभिन्न आदेशों के अनुसार, कार्यकारी अभियंता 2 को स्ट्रीटलाइट, जल आपूर्ति (घ्त./श्ख) का प्रभारी बनाया गया है।), सीवेज डी. वर्क्स (घ्त./श्ख) दस वर्षों से अधिक समय से खाते में कर्तव्यों का पालन कर रहा है। सहकारी समितियाँ इस स्थान के लिए हमारी क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही इतने लंबे समय से शुल्क ले रही हैं। किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त चार्ज भत्ता नहीं है। वडोदरा निगम में इंजीनियरिंग स्तर के साथ-साथ प्रशासनिक स्तर के विभिन्न पदों को भरने के लिए पिछले 15 वर्षों में कार्रवाई की गई है, लेकिन इलेक्ट्रिकल स्नातक के लिए कक्षा -1 की लंबे समय से चली आ रही रिक्ति को भरने या नए पद सृजित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डाक।

कार्यपालक अभियंता (विद्युत) पद हेतु दिनांक 5/10/2024 को आयोजित होने वाली कार्यपालक लिखित परीक्षा को रद्द करने हेतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। वर्ष 2015-16 से बाहर से सीधी भर्ती के माध्यम से कार्यकारी अभियंता (इलेक्ट्रिकल) के एक रिक्त पद को भरने के लिए एक लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके बाद लिखित परीक्षा रद्द कर सीधे इंटरव्यू आयोजित किया गया लेकिन पूरी भर्ती प्रक्रिया बिना किसी कारण के रद्द कर दी गयी.

जबकि वडोदरा नगर पालिका के अनुमोदित भर्ती नियमों के अनुसार कार्यकारी अभियंता (इलेक्ट्रिकल) के पद को भरने के लिए, भर्ती का मानक 1: 1 अनुपात है जो (1) सीधी भर्ती (2) आंतरिक भर्ती है, यह पद पहले सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता था, इसलिए अब यह पद आंतरिक भर्ती से भरा जाना है। हालांकि, वडोदरा नगर निगम नियम के तौर पर पुरानी प्रथा का ही पालन कर रहा है। वडोदरा निगम में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों की गलत व्याख्या कर कर्मचारियों एवं इंजीनियरों की भर्ती में दोहरी नीति के कई मामले चर्चा में रहे हैं।

वडोदरा निगम में सिटी इंजीनियर का एक पद है, जिसे आंतरिक भर्ती के माध्यम से प्रसारित किया गया था, हालांकि भर्ती मानदंड 1: 1 अनुपात था। जबकि निगम में 2022 तक कार्यपालक अभियंता (विद्युत) का एक पद स्वीकृत किया गया था. भले ही भर्ती मानक 1:1 अनुपात था, फिर भी इसे सीधी भर्ती द्वारा बाहर से भरने का विज्ञापन दिया गया था। जिसके क्रम में चार वर्ष बीत जाने के बाद दिनांक 5/10/2024 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया है।

निगम के पास उप कार्यपालक अभियंता से कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रोन्नति का कोई मानक नहीं है. वर्ष 2016 में, एसके नायक 1992 में उप अभियंता (एमसी) के रूप में वडोदरा नगर निगम में शामिल हुए और बाद में उन्हें कार्यकारी अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया। फिर उन्हें बिना किसी भर्ती प्रक्रिया के सीधे ए.डी.सी.टी.इंजीनियर के लिए कार्यपालन अभियंता (मैकेनिकल) पद के लिए नाम प्रस्तावित कर दिया गया और स्वीकृत कराकर ए.डी.सिटी इंजीनियर बना दिया गया। नाका में 27 वर्ष का अनुभव रखने वाले तथा 10 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले अभियंताओं को विभिन्न लेखा में कार्यपालक अभियंता के प्रभार में नामांकित कर कार्यपालक अभियंता 2 की नियुक्ति हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी है.

अस्सी मु. बैठक में आयुक्तों के अतिरिक्त पदों को मंजूरी देकर शासन की मंजूरी न मिलने के बावजूद इन पदों पर नियुक्तियां कर दी गईं। हालाँकि25-08-2022से कार्यकारीअभियंता (इलेक्ट्रिकल) का एक अतिरिक्त पद स्वीकृत किया गया है यानी दो वर्षों से कार्यकारी अभियंता (इलेक्ट्रिकल)केकुल दो पद स्वीकृत हैं, लेकिन इस पद को भरने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

भारी बारिश के कारण वडोदरा के खोडियार नगर क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात

वडोदरा,28 सितंबर

मानसून का मौसम अभी खत्म नहीं हुआ है. गिनती के दिन शेष रहते खिलाड़ी झील में नवरात्र की तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन बारिश के पानी में गरबा खेला जाएगा या डिस्को होगा, इसे लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जबकि कल दिन में भी बारिश का मौसम जारी रहा, कभी-कभी धीमी और लगातार बारिश होती रही. लेकिन रात के दौरान भारी बारिश के कारण आधा इंच पानी भर गया, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई, जिससे वार्ड 4 में पिछली बाढ़ की याद आ गई, जहां पूरा कैडेट जलमग्न हो गया था।

कल दिन भर सूरज और बादलों के बीच लुकाछिपी का खेल चलता रहा और बीच-बीच में बारिश की फुहारें भी पड़ती रहीं। देर शाम अचानक हुई बारिश के बाद शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। उधर, वार्ड के चार वार्डों में बारिश का पानी भर जाने से स्थानीय लोगों को पिछली बाढ़ की याद ताजा हो गयी. सड़क पर बारिश का पानी होने के कारण कई गाड़ियां फंस गईं और लोगों को धक्के खाने को मजबूर होना पड़ा. कल रात की बारिश में लगभग आधा इंच पानी आया। हालाँकि, स्थानीय निवासियों ने नगरपालिका प्रणाली पर मछलियाँ धोना शुरू कर दिया क्योंकि बिक्री क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में पानी भर गया था।

प्रदेश में चलती बस में महिला से दुष्कर्मः 'बेटे को जान से मारने की दी धमकी'

सूरत,28 सितंबर

रेप की घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं, वहीं अमरेली के लाठी में एक लग्जरी बस के ड्राइवर द्वारा महिला से रेप करने की घटना सामने आई है. लाठी से सूरत जा रही निजी बस के ड्राइवर ने बेटे को जान से मारने की धमकी देकर महिला से दो बार दुष्कर्म किया। महिला ने कपोदरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है और आरोपी को पकड़ने के लिए आगे की जांच की जा रही है।

प्राप्त विवरण के अनुसार, सूरत के परवत पाटिया इलाके की महिला ने अमरेली के लाठी स्थित अपनी बहन के घर जाने के लिए मारुति नंदन ट्रेवल्स की एक लक्जरी बस में यात्रा की।

बस चलने के दौरान बस के ड्राइवर ने महिला के साथ रेप किया. उन्होंने इस बारे में किसी को बताने पर उसे और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। बहरहाल, इस घटना को लेकर पीड़ित महिला ने सूरत के कपोदरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस अब मामले की आगे की जांच में जुट गई है.

पीड़ित महिला ने शिकायत में बताया कि उसका सात साल का बेटा लाठी में रहने वाली अपनी बहन से मिलने के लिए मारुति नंदन की लग्जरी बस में गया था. निर्धारित स्थान पर पहुंचने के बाद बस चालक ने महिला को बुलाया और दोस्ती करने के लिए दबाव डाला। जिसके बारे में महिला ने साफ मना किया था. हालाँकि, अगले दिन, जब वही बस फिर से सूरत के लिए रवाना हुई, तो ड्राइवर ने उस स्थिति का फायदा उठाया जब सभी यात्री सो रहे थे और बेटे को जान से मारने की धमकी दी और धमकी दी कि अगर उसने किसी के साथ ऐसा किया तो वह उसे मार देगा।

विश्वामित्री नदी के किनारे एगोरा मॉल के अवैध क्लब हाउस को तोड़ने में लगेंगे तीन दिनः अगले दिन भी काम जारी

वडोदरा,28 सितंबर,

विश्वामित्री नदी के तट पर वडोदरा नगर निगम द्वारा अवैध रूप से बनाए गए बालाजी समूह के अगोरा मॉल के 30,000 वर्ग फुट के क्लब हाउस ढांचे का विध्वंस तीन दिनों तक चलेगा। कल से शुरू हुआ जो आज भी जारी रहा और कल तक भी जारी रहा. जबकि एगोरा मॉल की रिटेनिंग वॉल की स्थिरता की जांच करने के बाद इसे ध्वस्त करने पर निर्णय लिया जाएगा।

निगम ने वडोदरा शहर के मध्य से गुजरने वाली विश्वामित्री नदी के तट पर एक निजी कंपनी और ड्रोन से निर्माण सर्वेक्षण कराया। जिसकी रिपोर्ट हाल ही में नगर आयुक्त को सौंपी गई है। फिर मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा. सयाजीगंज विधायक केयूर रोकड़िया ने नदी किनारे अवैध निर्माण पर मार्गदर्शन मांगा, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री ने आयुक्त को दबाव तोड़ने का निर्देश भी दिया. इसके बाद निगम ने 13 अवैध निर्माणों को नोटिस जारी कर 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया।

इसी क्षेत्र में बालाजी ग्रुप द्वारा बनाए गए एगोरा मॉल के 30,000 वर्ग फुट के क्लब हाउस को तोड़ने की कार्रवाई वडोदरा कॉर्पोरेशन द्वारा शुरू की गई थी। जो आज दूसरे दिन भी जारी है. अब जबकि रिटेनिंग वॉल बन चुकी है और नदी तल में लगभग 15 से 20 मीटर काम पूरा हो चुका है, तो दीवार को तोड़ना है या नहीं, इस पर क्षमता रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी।

यहां यह याद दिलाना जरूरी है कि राज्य सरकार ने विश्वामित्री परियोजना के लिए 1200 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं. इसे ध्यान में रखते हुए निगम ने एक निजी कंपनी और ड्रोन के जरिए सर्वे कराया। हाल ही में निजी कर्मचारियों की अलग-अलग टीमों ने हरानी से मुजामहुदा तक सर्वेक्षण किया। सर्वे करने के बाद नगर आयुक्त ने बैठक कर आगे की प्रक्रिया पर चर्चा की.

सर्वे केबाद 13 दबाव पाए गए. जिसकेमद्देनजरसयाजीगंजके विधायक कयूर रोकड़िया ने मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और जिस तरह द्वारका, सोमनाथ और मुख्यमंत्री में बुलडोजर चलाया गया था, उसी तरह वडोदरा के कांथा क्षेत्र में अवैध निर्माणोंको ध्वस्त करने का प्रस्ताव रखा। मंत्री मुन. आयुक्त दिलीप राणा ने सर्वे कार्य के अनुसार दबाव तोड़ने के निर्देश दिये.

वडोदरामें अकोटा-अलकापुरी की ओर गोवर्धन नाथजी हवेलीरोड पर एक औरभूस्खलन हुआ

वड़ोदरा, 28 सितंबर

कला नगरी के नाम से मशहूर वडोदरा अब संस्कार नगरी, मगर नगरी और भुवा नगरी के नाम से जाना जा रहा है, वहीं शहर के पश्चिमी इलाके में गोवर्धननाथजी की हवेली से अकोटा-अलकापुरी की ओर जाने वाले रास्ते पर एक और गड्ढा हो गया है. इससे पहले कि ड्राइवर सड़क पार कर वापस लौट पाता, कुछ ही मिनटों में उसकी कार मलबे में लटकी मिली, मलबा इतना बड़ा है कि पूरी कार को अपनी चपेट में ले सकता है। भ्रष्ट नगरपालिका प्रणाली में भ्रष्टाचार का एक और स्तंभ उजागर हुआ है क्योंकि कार चालक ने सावधानी बरती और अन्य राहगीरों की मदद से कार को भुवा से सुरक्षित बाहर खींच लिया।

गौरतलब है कि शहर में हर दिन एक यादो भुवा गिरने की खबर अब नई नहीं है। लोग भी अब अपने वाहन यहजानने के बाद ही ले जाते हैं किवे किस रास्ते पर हैं। अकोटा-अलकापुरी रोड पर गोवर्धननाथजी हवेली के रोड डिवाइडर के पास ट्रैफिक सिग्नल बंद होने पर एक कार चालक नेअपनी कार चालू रखी और सड़क को विपरीत दिशा में पार कर गया। जब वह वापस आया तो अपनी कार का पहिया जमीन में लटका हुआ देखकर हैरान रह गया। जमीन धंसने के कारण कार के नीचे की जमीन इतनी बड़ी हो गई है कि कुछ ही मिनटों में पूरी कार उसमें समा गई।

अपने कार्य को लेकर लगातार चिंतन करते रहना ही 'कर्मयोगी' और 'चिंतन शिविर' की संकल्पना का मर्म है : मुख्यमंत्री

अहमदाबाद (ईएमएस)मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए शनिवार को भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद (आईआईएमए) में आयोजित एक दिवसीय चिंतन शिविर का उद्घाटन करते हुए भूपेंद्र पटेल ने कहा कि हम सभी को अपने अंदर चिंतन करने की आदत विकसित करनी चाहिए। हम जो भी कार्य करें, उस पर समय-समय पर चिंतन करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमें 'कर्मयोगी' और 'चिंतन शिविर' की संकल्पना दी है, उसका मर्म ही यह है कि जो कुछ भी हम करें, उस विषय में चिंतन या विचार करें। उन्होंने कहा कि चिंतन करने से किसी भी काम को और भी बेहतर तरीके से करने की आदत विकसित होती है। जब कोई चिंतन नहीं होता, तभी समस्याएं खड़ी होती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपने कार्य और कार्य करने की हमारी पद्धति को लेकर चिंतन करना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति के साथ तुलना किए बिना अपनी भूमिका को अच्छे से निभाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीखने, पढ़ने और ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। ऐसे चिंतन शिविर के पीछे का मर्म भी यही है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि सेवा और भाव का सकारात्मक समन्वय जरूरी है। मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करने वाले लोगों के आचरण-व्यवहार पर पूरे राज्य के लोगों की नजर रहती है, इसलिए हमारी विशेष जिम्मेदारी है। आपका आचरण ही सीएम कार्यालय का प्रतिबिंब है। भूपेन्द्र पटेल ने कहा कि बदलते समय में लोगों की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हम सभी को और अधिक तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि हम सभी को जनसेवा करने का अवसर मिला है, तब यह आवश्यक है कि हम एक अच्छे ट्रस्टी के रूप में सेवा भाव से अपनी भूमिका निभाएं।

चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री की सचिव श्रीमती अवंतिका सिंह ने कहा कि चिंतन शिविर में लर्निंग और शेयरिंग के अलावा टीम बॉन्डिंग भी बढ़ती है। मुख्यमंत्री कार्यालय की भूमिका निर्णायक होती है, तब ऐसे शिविरोंकेमाध्यम से सभी अधिकारियोंऔरकर्मचारियों में प्रो-एक्टिव और प्रो-पीपल दृष्टिकोण विकसित करने का काम भी हो सकता है। श्रीमती सिंह ने पिछले चिंतन शिविर का उल्लेख करते हुए कहा कि उस चिंतन शिविर के बाद सभी की ऊर्जा बढ़ गई थी, और तत्परता के साथ-साथ दृष्टिकोण में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिले थे। बदलते समय में अनेक अनिश्चितताओं, लगातार सामने आती समस्याओं और विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के बीच तैयारी, टीम वर्क और प्रो-एक्टिव दृष्टिकोण के जरिए ही मुख्यमंत्री कार्यालय की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह चिंतन शिविर इस दिशा में आगे बढ़ने में फलदायी सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार और स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप संस्थान के उपाध्यक्ष हसमुख अढिया ने 'टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट' विषय पर एक सत्र का संचालन किया। अढिया ने स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी तनाव प्रबंधन के लिए कुछ टिप्स देते हुए पारिवारिक संबंधों, पर्याप्त नींद, ध्यान और कर्म के सिद्धांत समझने पर जोर दिया। उन्होंने पीओआरटी (पजेशन, ऑब्लिगेशन, रिलेशन और ट्रांजेक्शन) थ्योरी पर भी प्रकाश डाला।

चिंतन शिविर के अंत में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिवों पंकज जोशी तथा एम.के. दास ने अपने अनुभव और विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह एक दिवसीय चिंतन शिविर मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मयोगियों के लिए उनके कामकाज और कार्यदक्षता में उपयुक्त बनेगा।

मुख्यमंत्र आज वडोदरा में, लघु उद्योग भारती के क्षेत्रीय सम्मेलन का उदघाटन करेंगे

वडोदरा (ईएमएस)मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल कल 29 सितंबर 2024, रविवार को सुबह 11:30 बजे सयाजी हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में लघु उद्योग भारती गुजरात प्रदेश वडोदरा जिले द्वारा आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।

लघु उद्योग भारती देश का सबसे बड़ा औद्योगिक संगठन है जो उद्योग से राष्ट्रहित के मंत्र के साथ पिछले 29 वर्षों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के हित में काम कर रहा है। वडोदरा में आयोजित कार्यक्रम में गुजरात के विभिन्न हिस्सों से लघु उद्योगों से जुड़े 500 से अधिक सदस्यों के शामिल होने की उम्मीद हैं लघु उद्योग भारती के क्षेत्रीय सम्मेलन कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं। कार्यक्रम में लघु उद्योगों के सामने आने वाली कठिनाइयों और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम कल सुबह 11 बजे से शुरू होगा और पूरे दिन चलेगा

ऊपरी इलाकों में बारिश के कारण आजवा झील का स्तर 11:00 बजे 212.05 दर्ज किया गया

वड़ोदरा 28 सितंबर

वड़ोदरा अजवा झीलः वड़ोदरा में शुक्रवार आधी रात को भारी बारिश हुई. वहीं वडोदरा को पीने का पानी सप्लाई करने वाली अजवा झील में भी 24 घंटे में करीब चार इंच बारिश हुई है, जिससे अजवा झील का स्तर काफी बढ़ गया है.

आज सुबह 11:00 बजे मौजूदा स्तर 212.05 फीट था. अजवा झील के अपस्ट्रीम, आसोज में 67 मिमी, धनसरवाव में 60 मिमी, हालोल में 40 मिमी बारिश दर्ज की गई है। तो आज झील की सतह और भी बढ़ जाएगी. हालांकि, फिलहाल गेट खोलने का कोई सवाल ही नहीं है। इसमें 214 फीट तक पानी भरा जा सकता है। विश्वामित्री को वर्तमान में अपस्ट्रीम में 1644 क्यूसेक पानी मिल रहा है, आज सुबह कालाघोड़ा में विश्वामित्री का स्तर 16 फीट दर्ज किया गया। पिछले दो दिनों में विश्वामित्री की सतह काफी ऊपर उठ गई है। शहर के मंगल पांडे ब्रिज पर लेवल 16.50 फीट, मुज महुदा ब्रिज पर 16.70 फीट और नागरवाड़ा ब्रिज पर 7 फीट था। सुबह छह बजे विश्वामित्री की सतह 14 फीट थी, यानी पांच से छह घंटे में सतह दो फीट ऊपर उठ गयी है. जबकि आज सुबह 6:00 बजे झील का लेवल 211.90 फीट था, इसमें भी बढ़ोतरी हो रही है. विश्वामित्री नदी का खतरनाक स्तर 26 फीट है, जबकि सतह से 10 फीट नीचे है।

भारी ट्रैफिक वाले वडोदरा के वाघोडिया रोड पर एक बुजुर्ग की गर्दन तोड़कर दो आरोपी फरार हो गए.

वड़ोदरा,28 सितंबर

वड़ोदरा में वाघोडिया रोड पर परिवार चार रास्ता के पास अमीदर्शन सोसायटी में रहने वाली 69 वर्षीय रंजनबेन किरण बाबूभाई जोशी कल शाम पौने छह बजे घर से पूनम कॉम्प्लेक्स के पास रणछोड़जी के मंदिर में दर्शन करने गईं। दर्शन करने के बाद वह कला दर्शन चार रोड के पास सब्जी खरीदने के लिए लॉरी पर खड़े थे. बाद में जब वे सब्जी लेकर घर की ओर जा रहे थे, तभी दो आरोपी दोपहिया वाहन पर गलत साइड से आए और वृद्ध के गले से सोने की चेन तोड़कर भाग गए। वृद्ध चिल्लाया लेकिन आरोपी भागने में सफल रहा। आरोपी द्वारा आधा तोले की सोने की चेन तोड़कर भागने के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है।

शेड में आग लगने से एक श्रमिक की मौत की घटना में निर्माता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है

सूरत,28 सितंबर

सरथाणा सीमाडा वालमनगर में पत्थर चिपकाने वाली शीट बनाने वाली इकाई के शेड में आग लगने से एक श्रमिक की मौत की घटना में सरथाणा पुलिस ने किराए पर खाताचलानेवाले कारखाने के मालिक के खिलाफलापरवाही का मामला दर्ज किया है घटना के समय बगल में रखे केमिकल केकारण कोई अग्नि सुरक्षा उपकरणनहीं था और देखते ही देखतेआगनेभयानकरूप ले लिया।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मकाननंबर102 की दूसरी मंजिल परपत्थर चिपकाने वाली शीट बनानेवालीइकाई के शेड में अचानक आग लगने सेउद्योगपति जयेश वसोया समेत 9 लोग झुलस गये, इनमें से परेशगोबिंदवसोयाकीमौतहोगयी. इससंबंध में सूरत शहरकेबाहरी इलाके सीमाड़ा नाका वालमनगर में अविनाश समीरभाई वसावा (21, मूल निवासी चितलदा, जिला उमरपाड़ा, सूरत) जो तीन दिन पहले साड़ियों में हीरे जड़ने का काम करता था। फैक्ट्री कर्मचारी जयेशभाई बाबूभाई वसोया (निवासी मकान नंबर .65, सविखा रो हाउस, सीमाड़ा गांव, सरथाणा, सूरत) ने सरथाणा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई है।

सरथाणा सीमाडा में स्टोन पेस्ट शीट निर्माण इकाई में किराए पर खाता चलाने वाले जयेश वसोया ग्राइंडर मशीन से केमिकल को पतला कर रहे थे, तभी आग लगने से पास का केमिकल जलगया। तीसरी मंजिल पर स्थित पेपर शेड में कोई अग्नि सुरक्षा उपकरण नहीं था और गणना के समय आग ने भयानक रूप ले लिया। - सरथाणा सीमाड़ा में स्टोन स्टिकिंग शीट निर्माण इकाई में किराए पर खाता चलाने वाले जयेश वसोया ग्राइंडर मशीनसेकेमिकल को पतला कर रहे थे, तभीआग लगने से पास का केमिकल जल गया।तीसरी मंजिल पर लेटर शेड में चल रहे खाते में आग से सुरक्षा के कोइउपकरण नहीं थे, गणना के दौरान आग ने भयानक रूप ले लिया और हादसा हो गया।

उन्होंने शिकायत में कहा कि कल सुबह जब सभी कर्मचारी काम कर रहे थे,तब फैक्ट्री में किराये पर खाता चलाने वाला कर्मचारी जयेश वसोया शीट बनाने वाली मशीन के बगल में प्लास्टिक बैरल में रखे केमिकल को ग्राइंडर मशीन से पतला कर रहबजेउनके हाथ से निकल गया और उसमें मौजूद केमिकल में शॉर्ट सर्किट हो गया और आग कुछ ही मिनटों में साड़ी की दुकान में फैल गई और वहां कोई अग्नि सुरक्षा उपकरण नहीं था

वडोदरा में देर रात हुई बारिश से दो घर ढह गए, चार घर पेड़ों के नीचे दब गए

वड़ोदरा,28 सितंबर

वड़ोदरा हाउस ढह गयाः वड़ोदरा में कल देर रात भारी बारिश के कारण कई जगहों पर पेड़ और घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

वादी मुगलवाड़ा और फतेपुरा पौवा वालानी गली में मकानों के कुछ हिस्से गिरने से फायर ब्रिगेड की मदद ली गई। दोनों घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ और फायर ब्रिगेड द्वारा यातायात रोक दिया गया है।

अलग-अलग इलाकों में करीब एक दर्जन पेड़ गिर गए और फायर ब्रिगेड ने पेड़ हटाने का काम शुरू कर दिया है. कारेलीबाग बहुचराजी रोड पर बरगद के पेड़ से चार घर दब गये और उनमें रहने वाले चार लोग आधे घंटे तक फंसे रहे. फायर ब्रिगेड द्वारा बचाव कार्य चलाया गया।

स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि बरगद का पेड़ गिरने का खतरा है और उन्होंने निगम को आवेदन दिया है लेकिन हमारी याचिका पर ध्यान नहीं दिया गया।

गुजरात में कृषि प्रौद्योगिकी पर प्रमुख प्रदर्शनी एग्री एशिया 2024 के 13वें संस्करण का सफल समापन

कृषि प्रौद्योगिकी पर प्रमुख प्रदर्शनी -13वीं एग्री एशिया2024, 20 से 22 सितंबर 2024 तक हेलीपैड प्रदर्शनी केंद्र, गांधीनगर, गुजरात में आयोजित की गई थी। ठउन्नत तकनीक से कृषि का अनुभवठ(,ठ(ॅजेगहम ॅउॅंघ्ळथ्ऊळॅं ॅगू ॅअॅंन्ॅंऊॅं ऊॅंण्ध्थ्थ्उभ) थीम के तहत आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रदर्शनी ने कृषि प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रदर्शित किया और कृषि उद्योग से जुड़े हुए सभी के लिए मूल्यवान नेटवर्किंग के अवसर प्रदान किए।200से अधिक प्रमुख प्रदर्शकों और 90,000 से अधिकआगंतुकों ने 15,000 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल को फेले तीन बड़े हॉलों में आयोजित आधुनिक तकनीक प्रस्तुत करने वाली प्रदर्शनी का दौरा किया। इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 5,000 से अधिक नए उत्पाद पेश किए गएकृषि उद्योग में अत्याधुनिक तकनीक, अग्रेताओ के साथ बातचीत, वितरकों, डीलरों और हितधारकों के साथ नेटवर्किंग की नई दिशा दिखाने वाली प्रदर्शनी रही।

कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त जानकारी और अवसर प्रदान करने हेतुसर डेयरी पशुधन और पोल्ट्री एक्सपो (डीएलपीई) एग्री एशिया 2024 के संयोजन में आयोजित किया गया था। मेले में किसानों एवं पशुपालकों के लिए नई तकनीक, उन्नत पद्धति एवं कृषि उत्पादकों एवं पालन के लिए उपयोगी जानकारी के विभिन्न स्टॉल लगाए गए थे।साथ ही इस वर्ष पशु प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें गायों में कांकरेज़ , गिर और डांगी तथा भेसो में बन्नी, मेहसानी और जाफराबादी के बीच प्रतियोगिता हुई, जिसमें भवानी प्रजनन फार्म की कांकरेज़ गाय माता प्रथम स्थान पर रहीं।विजेताओं को प्रोत्साहन स्वरूप प्रथम पुरस्कार के लिए 71,000, द्वितीय के लिए 55,000 और तृतीय के लिए 31,000 का पुरस्कार दिया गया।ड्रोन प्रौद्योगिकी के लाइव प्रदर्शन और पशु प्रदर्शन के साथ-साथ कृषि और डेयरी किसानों के लिए विशेष सेमिनार भी आयोजित किए गए थे ।

आईएसबी (ISB)ने 'पीजीपी वाई एल' (PGP YL) लॉन्च किया

राष्ट्रीय, सितंबर, 2024: 2001 में स्थापित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी), मैनेजमेंट एजुकेशन में नए मानक स्थापित करने के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत एवं विश्व के लिए भविष्य के लीडर तैयार करने के अपने मिशन की ओर एक और बड़ी पहल शुरू कर रहा है। आईएसबी ने 2 साल तक के फुल टाईम वर्क एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए 20 माह का फुल टाईम एमबीए इक्विवेलेंट रेजिडेंशियल मैनेजमेंट प्रोग्राम- पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट फॉर यंग लीडर्स (पीजीपी वाईएल) (इउइ भ्थ) शुरू किया है।

नए पीजीपी वाईएल (इउइ भ्थ) प्रोग्राम के बारे में प्रोफेसर मदन पिलुटला, डीन, आईएसबी ने कहा, ''आईएसबी (घ्एँ) 2001 में अपनी शुरुआत से ही विश्वस्तर की मैनेजमेंट शिक्षा प्रदान कर रहा है और भारत एवं विश्व के लिए लीडर्स का निर्माण कर रहा है। इंडस्ट्री के लीडर्स और नियोक्ताओं के साथ हमारी वार्ताओं में ऐसे युवा प्रोफेशनल्स की जरूरत सामने आई, जो सीधे ऐसे पदों पर काम कर सकें, जिनके लिए व्यवसायिक कौशल के साथ डेटा एवं टेक्नोलॉजी में गहरी विशेषज्ञता की जरूरत हो। इन आवश्यकताओं के अनुरूप हमने नए ग्रेजुएट्स एवं एंट्री लेवल प्रोफेशनल्स के लिए पीजीपी वाईएल (इउइ भ्थ) प्रोग्राम का डिज़ाईन किया है, जो उन्हें कार्यस्थल पर असाधारण प्रॉब्लम सॉल्वर और इनोवेटर के रूप में तब्दील कर देगा।''

पश्चिम रेलवे विभिन्न स्थानों के लिए साप्ताहिक त्योहार विशेष ट्रेनें चलाएगा

ट्रेन नं.	मूल स्टेशन और स्थान	सेवा की तिथि	प्रस्थान	आगमन
09027	बांद्रा टर्मिनस – मालदा टाउन	02/10/2024 से 27/11/2024	11:00 बजे (बुधवार)	17:30 बजे (शनिवार)
09028	मालदा टाउन–बांद्रा टर्मिनस	05/10/2024 से 30/11/2024	16:30 बजे (शुक्रवार)	18:15 बजे (सोमवार)
हॉल्ट- बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना, आगरा किला, टूंडला, इटावा, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, नरकटियागंज, बापूधाम मोतिहारी , मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी, किऊल, अभयपुर, जमालपुर, सुल्तानगंज, भागलपुर, कहलगांव, साहिबगंज, बरहरवा और न्यू फरक्का स्टेशन दोनों दिशाओं में।				
संरचना: एसी 3–टियर, स्लीपर क्लास और सामान्य द्वितीय श्रेणी कोच।				
09031	बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर	03/10/2024 से 28/11/2024	12:15 बजे (गुरुवार)	21:00 बजे (अगले दिन)
09032	गोरखपुर–दहानू रोड	05/10/2024 से 30/11/2024	04:00 बजे (शनिवार)	12:25 बजे (अगले दिन)
हाल्ट: वापी, वलसाड, उधना, भरूच, वडोदरा, रतलाम, उज्जैन, संत हिरदाराम नगर, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, मनकापुर, बस्ती और खलीलाबाद स्टेशन दोनों दिशाओं में। ट्रेन संख्या 09031 का बोरीवली, पालघर, दहानू रोड और गोधरा स्टेशनों पर अतिरिक्त				
संरचना: एसी 3–टियर, स्लीपर क्लास और सामान्य द्वितीय श्रेणी कोच				
09013	उधना–छपरा	05/10/2024 से 30/11/2024	07:00 बजे (शनिवार)	19:30 बजे (अगले दिन)
09014	छपरा–उधना	06/10/2024 से 01/12/2024	22:30 बजे (रविवार)	08:15 बजे (मंगलवार)
हाल्ट: भरूच, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, उज्जैन, संत हिरदाराम नगर, बीना, सागर, दमोह, कटनी मुरवारा, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, औरिहार, गाज़ीपुर सिटी और बलिया स्टेशन दोनों दिशाओं में।				
संरचना: एसी 2–टियर, एसी 3–टियर, स्लीपर क्लास और सामान्य द्वितीय श्रेणी कोच।				
09457	अहमदाबाद – दानापुर	06/10/2024 से 24/11/2024